

बाजार का हाल		
मार्केट	बंद	गिरावट
सेसेक्स	80,710.25	308.47 ▼
निफ्टी	24,649.55	73.20 ▼
धातु	कीमत	तेजी
सोना	98,820/-	800/- ▲
चांदी	1,12,000/-	2000/- ▲
(सोना प्रति 10 ग्राम और चांदी प्रति किलो रु. में)		
मुद्रा	प्रति डॉलर	नीचे
रुपया	87.82	16 पैसे ▼
कूड ऑयल	68.09 बैरल	0.97% ▼
पेट्रोल दिल्ली में 94.72 रु. लीटर और डीजल 87.62 रु. लीटर बिक रहा है।		



79 साल की उम्र में ली अंतिम सांस, किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे

जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक नहीं रहे उनके कार्यकाल में आज ही के दिन हटा था अनुच्छेद 370

अंतिम संस्कार आज दिल्ली में, तबीयत बिगड़ने के बाद 11 नई को करवाया था अस्पताल में भर्ती, कई बयानों को लेकर विवादों में भी रहे

नई दिल्ली (भाषा)। जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का लंबी बीमारी के बाद मंगलवार को यहां राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल में निधन हो गया। वह 79 वर्ष के थे। मलिक के निजी स्टाफ ने मंगलवार को यह जानकारी दी। मलिक लंबे समय से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। 11 नई को हालत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वे बिहार, गोवा और मेघालय के राज्यपाल रहे। 2018 में ओडिशा के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला। सत्यपाल 23 अगस्त 2018 से 30 अक्टूबर 2019 तक जम्मू-कश्मीर के उप राज्यपाल रहे। उनके कार्यकाल के दौरान आज ही के दिन यानी 5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को निरस्त कर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था। संयोग से, उन्होंने केंद्र के इस कदम के 6 साल पूरे होने के दिन अंतिम सांस ली। उनके निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी समेत तमाम नेताओं ने शोक जताया।

कई बीमारियों से परेशान थे

आरएमएल के अधिकारियों ने कहा, 'गहरे दुख के साथ, हम सत्यपाल मलिक के निधन की पुष्टि करते हैं। उनका हमारे अस्पताल की गहन देखभाल इकाई में इलाज किया जा रहा था। मलिक मधुमेह, गुर्दे की बीमारी, उच्च रक्तचाप और मोटापा एवं नौद के रक्तचाप जैसी स्वास्थ्य समस्याओं से लंबे समय से जूझ रहे थे। (पेज 8 भी देखें)

भाजपा सरकार के खिलाफ बयान देकर चौकाया

2 नवंबर 2021: पुलवामा अटैंक के वक्त पीएम नरेन्द्र मोदी कॉन्फिड नेशनल पार्क में अपनी शूटिंग करवा रहे थे। बाहर आकर पीएम ने एक दाबे से फोन कर मुझे पूछा- क्या हुआ? मैंने कहा था- ये हमारी गलती से हुआ। तब मुझे चुप करवा दिया गया।
25 अप्रैल 2023: देश बहुत गलत दिशा में बढ़ रहा है। यदि किसान एक नहीं हुआ और केंद्र में बैठी सरकार देबाबा सत्ता में आई तो किसान नहीं बचेंगे। वे सबसे पहले खेती खत्म कर देंगे। ताकि आप मजदूरी करने लगे। उसके बाद फौज को खत्म कर देंगे।
21 मई 2023: अगर अगले चुनाव तक जनता ने इनके खिलाफ मतदान नहीं किया तो ये आपको मतदान करने लायक ही नहीं छोड़ेंगे। ये कह देंगे कि जब हम ही चुनाव जीतते हैं तो चुनाव कराने की क्या जरूरत। न कोर्ट रहेंगे न फोर्स रहेंगे न फौज होगी और न कोई ऐसा सिस्टम रहेगा, जिससे इन पर कंट्रोल किया जा सके।
22 मई 2023: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपनी नाक के नीचे झुकाकर करवाते हैं। उसमें इनकी हिस्सेदारी होती है और पूरी रकम अडानों को जाती है।
6 मई 2025: पहलगाम की असफलता के पीएम मोदी को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने अभी तक इसकी जिम्मेदारी नहीं स्वीकार की है।

पीएम मोदी ने शोक व्यक्त किया

पीएम नरेन्द्र मोदी ने पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के निधन पर शोक जताया। मलिक का लंबी बीमारी के बाद यहां एक अस्पताल में निधन हो गया। मोदी ने एक्स पर लिखा, '(मैं) श्री सत्यपाल मलिक जी के निधन से दुःखी हूँ। इस दुःख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और समर्थकों के साथ हैं।'



Muthoo Finance गोल्ड लोन

दुर्लभ गोल्ड लोन 7-स्तरीय सुरक्षा

आकर्षक व्याज दर

ऑनलाइन भुगतान की सुविधा

1800 313 1212

एसडीआरएफ-एनडीआरएफ और सेना, वायुसेना के जवान बचाव में जुटे

उत्तराखंड में बादल फटा, पूरा गांव जमींदोज, 4 की मौत, 50 लापता

खीर गंगा नदी में भीषण बाढ़, 34 सेकेंड में ही मकान-होटल सभी मलबे में दबे, 130 को बचाया

भाषा/एजेसी ►► उत्तरकाशी

उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली व सुक्की गांव में बादल फटने के कारण खीर गंगा नदी में बाढ़ आने से 34 सेकेंड में ही पूरा गांव जमींदोज हो गया। घर होटल सब कुछ मलबे में दब गया। अचानक आई इस आपदा में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग लापता होगा। बचाव दल ने 130 लोगों को बचा लिया है। हादसे के बाद हर तरफ चीख पुकार मच गई। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने कहा कि नुकसान का आकलन किया जा रहा है। सेना, राज्य आपदा प्रतिवादन बल (एसडीआरएफ), राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) तथा जिला प्रशासन की टीम राहत एवं बचाव कार्यों में जुटी हैं। प्रशासन का कहना है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। खीर गंगा नदी में पहाड़ों से बहकर आए मलबे से धराली का बाजार, मकान और होटल बह गए। सिर्फ 34 सेकेंड में सब कुछ बर्बाद हो गया। धराली गंगोत्री धाम से करीब 20 किलोमीटर पहले पड़ता है और यात्रा का प्रमुख पड़ाव है।



यह बोले प्रत्यक्षदर्शी
एक स्थानीय प्रत्यक्षदर्शी राजेश पंवार ने बताया कि खीर गंगा के जल गहन क्षेत्र के उपर बादल फटा जिसकी वजह से नदी में विनाशकारी बाढ़ आ गयी। सोशल मीडिया पर वाररल हो रहे एक वीडियो में दिखाई दे रहा है कि नदी में ऊपर से भारी मात्रा में तेजी से पानी और मलबा आया और देखते ही देखते मकान और होटल उसकी चपेट में आ गए।

लोग जान बचाकर भागे
इस आपदा के कई वीडियो सामने आए। इनमें लोग जान बचाने के लिए यहां-वहां भागते नजर आए। चारों तरफ चीख-पुकार मच गई। लोग इसके वीडियो बना रहे थे, वो लोगों से दूरी होने के बाद भी विल्ला-विल्लाकर बचने के लिए कह रहे थे। आपदा के बाद धराली में 30 फीट तक मलबा जम गया। बाजार की कई दुकानें और आसपास के मकान जमींदोज हो गए।

धराली गंगोत्री धाम से 18 किमी दूर
धराली गांव उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित एक छोटा पहाड़ी गांव है। यह गांव भागीरथी नदी के किनारे, हर्षिल घाटी के पास बसा हुआ है। धराली गांव गंगोत्री यात्रा का एक प्रमुख पड़ाव है। गंगोत्री धाम से 18 किमी दूर है। यहां से लोग आगे की कठिन चढ़ाई के लिए रुकते हैं।

पीएम मोदी ने ली जानकारी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक्स पर लिखा, 'मैं उत्तरकाशी के धराली में हुई इस त्रासदी से प्रभावित लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। इसके साथ ही, मैं सभी प्रभावित लोगों की कुशलता की कामना करता हूँ। मैंने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से बात की है और स्थिति को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी।'

सीएम धामी ने शोक जताया
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धराली में हुए भारी नुकसान पर दुःख जताया और प्रभावितों के प्रति संवेदना प्रकट की है। उन्होंने कहा कि धामी ने कहा कि वह निरंतर वरिष्ठ अधिकारियों के संपर्क में हैं और स्थिति को नियंत्रित जानकारी ले रहे हैं। पीड़ितों को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी।

खबर संक्षेप

105 करोड़ के घोटाले में पूर्व आईएस पर छापे

गुवाहाटी। ईडी ने असम राज्य शिक्षक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद में 105 करोड़ के घोटाले के सिलसिले में सेवानिवृत्त आईएस अधिकारी सेवाली देवी शर्मा और अन्य के खिलाफ छापेमारी की। सूत्रों ने बताया कि ईडी ने आठ परिसरों पर पीएमएलए के प्रावधानों के तहत छापे मारे हैं। भाषा

क्रिडो घोषाघड़ी में 42 करोड़ की संपत्ति कुर्क

नई दिल्ली। यूएस में क्रिडोकॉरेंसी एक्सचेंज 'काइनवेस' की नकल करने वाली एक फर्जी वेबसाइट के जरिये दो करोड़ अमेरिकी डॉलर की धोखाधड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार भारतीय व्यक्ति की 42.8 करोड़ की संपत्ति धन शोधन विरोधी कानून के तहत कुर्क की गई है। ईडी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। भाषा

मणिपुर में 6 माह और बढ़ेगा राष्ट्रपति शासन

नई दिल्ली। संसद ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन 6 माह और बढ़ाने के प्रावधान वाले सांविधिक संकल्प को मंजूरी दे दी। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन से संबंधित सांविधिक संकल्प को चर्चा एवं पारित करने के लिए उच्च सदन में पेश किया जिसके तहत राज्य में 13 फरवरी 2025 को लागू राष्ट्रपति शासन को 13 अगस्त से छह और महीने के लिए बढ़ाया है। भाषा

नांगलोई का रहने वाला था रोहित शोकीन

गुरुग्राम में दिल्ली के फाइनेंसर की ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या

गुरुग्राम (हरिभूमि न्यूज)। खेड़की दौला क्षेत्र में एसपीआर रोड पर दिल्ली से गुरुग्राम आए एक फाइनेंसर की बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी। फाइनेंसर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस की मांने तो मामले में परिजनों को सूचित कर दिया गया है। केस दर्ज कर जांच की जा रही है। प्रारंभिक तौर पर वारदात के पीछे का कारण प्रॉपर्टी विवाद सामने आया है। पुलिस टीम को घटनास्थल पर मृतक का भाई मिला। जिसने पुलिस को बताया उसका छोटा भाई रोहित शोकीन (39 वर्ष) निवासी कमरूदीन नगर, निहाल विहार (दिल्ली) प्रॉपर्टी डीलर व किराए का काम करता था। वह सोमवार को उससे गाड़ी मांगकर नोएडा जाने की कहकर गया था। जिसकी गुडगांव के सेक्टर-77 में पाम हिल्स सोसाइटी के सामने एसपीआर रोड पर पहुंचने पर बदमाशों ने फायरिंग कर हत्या कर दी।

बाइक पर आए थे आरोपित
प्रारंभिक पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपितों ने घटना स्थल पर सात-आठ गोलियां चलाई थीं। आरोपित बाइक पर सवार होकर आए थे। जिन्होंने रोहित पर ताबड़तोड़ गोलियां बलाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस टीम द्वारा आरोपियों की पहचान करके उन्हें गिरफ्तार करने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। फाइनेंसर रोहित शोकीन नांगलोई इलाके के रहने वाला था। कल्ल के बाद सामने आया त के हरियाणवी सिंगर राहुल यादव फाजिलपुरिया के फाइनेंसर हैं। हालांकि फाजिलपुरिया ने इससे इनकार किया है।



डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत को फिर 40 दिन की पैरोल

रोहतक (हरिभूमि न्यूज)। अपनी दो शिष्याओं से बलात्कार के मामले में 20 साल कारावास की सजा काट रहा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह 40 दिन की पैरोल मिलने के बाद रोहतक स्थित सुनारिया जेल से मंगलवार को बाहर आ गया। डेरे के प्रवक्ता और वकील जितेंद्र खुराना ने बताया कि गुरमीत सिंह पैरोल के दौरान सिरसा स्थित अपने डेरा मुख्यालय में रहेगा। सिंह ने सिरसा पहुंचने के बाद एक दुर्घटना के मामले में 20 साल की सजा काट रहा। गुरमीत 15 अगस्त को 58 साल का हो जाएगा। उसे 2017 में बलात्कार करने के मामले में दोषी ठहराया गया था।



रिहायशी एवं औद्योगिक क्षेत्रों का विकास होगा

प्रदेश के 5 जिलों में 35,500 एकड़ जमीन खरीदेगी सरकार

रेवाड़ी/पलवल (हरिभूमि न्यूज)। हरियाणा में 10 नए औद्योगिक शहर बसाने का सपना लेकर चल रही सरकार ने आईएमटी बनाने पर फोकस शुरू कर दिया है। प्रदेश सरकार रिहायशी एवं औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करने के लिए प्रदेश में 5 जिलों में 35,500 एकड़ भूमि अधिग्रहण करने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। बता दें कि रेवाड़ी, अनंजना, नारायणगढ़, जींद, रेवाड़ी और फरीदाबाद-पलवल में 5 नई आईएमटी बनेंगी। इन आईएमटी के लिए सरकार किसानों से 31 हजार एकड़ जमीन खरीदने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, फरीदाबाद में कई सेक्टरों का विस्तार किया जाएगा, जिसके लिए आसपास के एक दर्जन गांवों से 4500 एकड़ जमीन खरीदी जाएगी। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) रिहायशी और हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (एचएसएसआइडीसी) औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करने के लिए किसानों से 35,500 एकड़ भूमि खरीदेगी। खास बात यह कि किसानों की जमीन का जबरन अधिग्रहण नहीं किया जाएगा, बल्कि आनलाइन पोर्टल https://ebhoomi.jamabandi.nic.in के माध्यम से इस जमीन को खरीदा जाएगा। भूमि मालिक या भूमि संग्राहक अपनी रूचि, प्रस्ताव ई-भूमि पोर्टल पर 31 अगस्त तक कर सकते हैं।

खुलासा

पाक ने 1971 का युद्ध अमेरिका और चीन के हथियारों से लड़ा सोवियत संघ और फ्रांस ने पाक को किया था हथियार देने से इनकार

नई दिल्ली (भाषा)। रूस से कच्चा तेल खरीदने को लेकर अमेरिका की ओर से भारत की आलोचना के बीच, भारतीय सेना ने मंगलवार को अगस्त 1971 की एक समाचार क्लिप साझा की, जिसमें 1954 से पाकिस्तान को हथियार देने में अमेरिका की भूमिका को उजागर किया है। यह समाचार क्लिप सेना की पूर्वी कमान द्वारा सोशल मीडिया मंच 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में साझा की गई। पोस्ट में हैशटैग भारतीयसेना, पूर्वकमान, विजयवर्ष, 'लिबेरेशनऑफबांग्लादेश' और 'मीडियाहाइलाइट्स' के साथ ही इसमें नोफैक्स (तथ्यजानें) हैशटैग के साथ 'इस दिन उस वर्ष' युद्ध की तैयारी-05 अगस्त 1971 का भी उल्लेख किया है। यह समाचार 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध से कुछ महीने पहले प्रकाशित हुआ था। युद्ध के परिणामस्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ था।

1971 के अखबार की क्लिप साझा कर सेना ने अमेरिका पर किया प्रहार

पाक को 2 अरब डॉलर के मेजे गए थे हथियार
सेना की इंस्टॉक कमन ने एक्स पोस्ट में लिखा- 'इस दिन, उस साल, युद्ध की तैयारी 05 अगस्त 1971, फैक्ट जानें। 1954 से अब तक (1971) पाकिस्तान को 2 अरब डॉलर के अमेरिकी हथियार भेजे गए।' खबर में तत्कालीन रक्षा उत्पादन मंत्री वी.सी. शुक्ला का हवाला दिया है, जिन्होंने उस अवधि के दौरान आपूर्ति किए गए हथियारों के अनुमानित मूल्य के बारे में राज्यसभा को बताया था।

पाक ने अमेरिका-चीन के हथियारों से लड़ा युद्ध
5 अगस्त 1971 के अखबार की रिपोर्ट में उस समय के रक्षा उत्पादन मंत्री वी.सी. शुक्ला के बयान का जिक्र है। सोवियत संघ और फ्रांस ने पाक को हथियार देने से इनकार कर दिया, लेकिन अमेरिका ने समर्थन जारी रखा। अमेरिका और चीन ने पाक को हथियार सस्ती कीमतों पर बेचे थे। इससे यह साफ होता है कि भारत के खिलाफ 1971 का युद्ध पाकिस्तान ने इन्होंने देशों से मिले हथियारों से लड़ा था।

भारत को अपने साझेदार चुनने का हक : रूस
मास्को। रूस सरकार के प्रवक्ता दिमित्रो पेसकोव ने भारत के संबंध में अमेरिका की चेतावनियों पर टिप्पणी करते हुए कहा, 'हमारा मानना है कि संप्रभु देशों को अपने हितों के आधार पर व्यापार साझेदार, व्यापार और आर्थिक सहयोग में साझेदार स्वयं चुनने और स्वतंत्र रूप से व्यापार और आर्थिक सहयोग के तरीकों को निर्धारित करने का अधिकार होना चाहिए। ट्रंप के बयान के कुछ ही घंटों बाद, भारत ने रूस से कच्चे तेल की खरीद के लिए उसे 'अनुचित और अवैधपूर्ण' तरीके से निशाना बनाने को लेकर अमेरिका और यूरोपीय संघ पर पलटवार किया। भारत ने आलोचना को पुरजोर तरीके खारिज करते हुए अमेरिका और यूरोपीय संघ के रूस के साथ जारी व्यापारिक संबंधों की ओर ध्यान दिनाते हुए दोहरा मानदंड अपनाने की बात कही।

एसवाईएल पर नहीं बनी बात सुप्रीम कोर्ट जाएगा हरियाणा

पंजाब के सीएम मान की शर्त को केंद्र ने नकारा

डेढ़ घंटे चली बैठक में हर मुद्दे पर हुआ मंथन

हरिभूमि ब्यूरो ►► चंडीगढ़

सतलुज-यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर को लेकर मंगलवार को दिल्ली में हुई बैठक में पंजाब और हरियाणा के बीच बात नहीं बन पाई। करीब डेढ़ तक घंटे चली इस बैठक में पंजाब के सीएम भगवंत मान और हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी के साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने हर मुद्दे पर मंथन किया। बैठक के बाद हरियाणा के सीएम सैनी ने कहा कि पानी के मुद्दे को लेकर सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत हुई। अब हम 13 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में पॉजिटिव तरीके से अपना पक्ष रखेंगे और जवाब दायर करेंगे। बैठक में भगवंत मान ने फिर रावी नदी के पानी को लेकर अपनी बात रखी, लेकिन केंद्र ने इस पर अपनी असहमति जताई। इससे पहले हुई बैठक में मान ने स्पष्ट कर दिया था कि ये नहीं बनेगी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा था कि हरियाणा हमारा भाई है, हमें पानी मिलने पर आगे पानी सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है। मीटिंग से पहले सीएम मान और सीएम सैनी ने गले मिलकर एक-दूसरे का स्वागत किया।

चिनाब और रावी के पानी पर पंजाब का जोर
मान ने कहा कि बैठक से एक उम्मीद बनी है। पहलगाम अटैंक के बाद पाकिस्तान से रद्द हुआ इंडस वाटर समझौते का पानी पंजाब लाना जाए। झेलम का पानी पंजाब नहीं आ सकता है, लेकिन चिनाब और रावी का पानी आ सकता है। पौंग, रंजीत सागर डैम और भाखड़ा डैम में होते हुए ये पानी आ सकता है। इसके बाद हम हरियाणा को पानी देने के लिए तैयार है।

अगले 24 घंटे में भारत पर शुल्क में बढ़ोतरी करुंगा : ट्रंप न्यूयॉर्क

अगले 24 घंटे में भारत पर शुल्क में बढ़ोतरी करुंगा : ट्रंप न्यूयॉर्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि भारत एक अरब डॉलर का सामान नहीं रहा। वह अगले 24 घंटों में इस दक्षिण एशियाई देश पर शुल्क को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाएंगे। ट्रंप ने 'सोनेबर्न' रिवॉल्यूशन को दिए एक साक्षात्कार में कहा, 'भारत के बारे में लोग जो कहना पसंद नहीं करते, वह यह है कि वह सबसे ज्यादा शुल्क लगाने वाला देश है। उसका शुल्क किसी भी देश से ज्यादा है। हम भारत के साथ बहुत कम व्यापार करते हैं, क्योंकि उसके शुल्क बहुत ज्यादा हैं। इसलिए हमने 25 प्रतिशत शुल्क पर समझौता किया, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अगले 24 घंटों में इसे काफी बढ़ा दूंगा, क्योंकि वे रूस से तेल खरीद रहे हैं।

खबर संक्षेप



लिंगानुपात जुलाई के अंत तक बढ़कर 907
चंडीगढ़। हरियाणा में लिंगानुपात में सुधार हेतु राज्य कार्यबल (एसटीएफ) की साप्ताहिक बैठक यहां अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सुधीर राजपाल की अध्यक्षता में हुई। इस वर्ष 1 जनवरी से 31 जुलाई तक राज्य का लिंगानुपात सुधरकर 907 हो गया है, जो पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 899 था।

बसों का ट्रैकिंग सिस्टम 15 तक लागू : विज चंडीगढ़। परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि आने वाली 15 अगस्त तक बसों की ट्रैकिंग सिस्टम प्रणाली को लागू कर दिया जाएगा। इस संबंध में एक एप भी बनाई जाएगी, जिसके माध्यम से कोई भी यात्री यह देख सके कि उसकी बस कितने बजे आ रही है। इसके अलावा, रोडवेज में उपकरणों, सामान का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा। विज चंडीगढ़ में मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मैंने मंत्री बनते ही आदेश दिए थे कि हरियाणा की सारी बसों में ट्रैकिंग सिस्टम लगाया जाए।

डिजिटल पुलिसिंग में हरियाणा फिर नंबर वन
चंडीगढ़। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम की मासिक रैंकिंग में हरियाणा पुलिस ने एक बार फिर अपना परचम लहराते हुए पिछले 20 महीनों में 17वां बार देशभर में पहला स्थान हासिल किया है। इस उत्कृष्ट उपलब्धि पर पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने सीसीटीएसएफ की टीम को बधाई देते हुए कहा कि यह सफलता हरियाणा पुलिस की नई सोच, बेहतर कार्यप्रणाली और आधुनिक तकनीक के प्रभावी इस्तेमाल का परिणाम है।

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का कड़ा रुख

सांसदों और विधायकों के लंबित आपराधिक मामलों की स्टेटस रिपोर्ट मांगी, डीजीपी तलब

हरिभूमि न्यूज पंचकूला

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को आदेश दिया है कि वे वर्तमान और पूर्व सांसदों, विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की स्थिति रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत करें। इसके अलावा अब डीजीपी को वचुअली पेश होने को कहेंगे, ताकि वह स्वयं इसका स्पष्टीकरण दे सकें। चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस यशवीर सिंह राठौड़ की खंडपीठ इस मामले में स्वत संज्ञान लेते हुए सुनवाई कर रही है। यह कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2023 में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में की जा रही है, जिसमें सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे पर जोर दिया गया था। सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार की ओर से पेशा वकील ने बताया कि राज्य में

हाईकोर्ट ने सिविल सेवा उम्मीदवार को राहत दी, नियुक्ति से इनकार को 'अमान्य' माना

पंचकूला। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस विकास बहल ने हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के एक उम्मीदवार के पक्ष में फैसला सुनाया है। उम्मीदवार को चयन और हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा सिफारिश के बावजूद, 'दागी' बताकर सरकार ने नियुक्ति से इनकार कर दिया गया था। कोर्ट ने इस आधार को 'अमान्य' करार दिया है। इस फैसले से उम्मीदवार की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है, जिसमें उसे सांकेतिक वरिष्ठता और परिणामी सेवा लाभ भी मिलेंगे। जस्टिस बहल ने अपने फैसले में कहा, हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा चयन और नियुक्ति के लिए सिफारिश के बाद भी, राज्य द्वारा उम्मीदवार को 'दागी' मानकर नियुक्ति नहीं देने का आधार अमान्य है। अपीलकर्ता को उन समान स्थिति वाले व्यक्तियों के साथ समानता का अधिकार है, जिन्हें नियुक्ति दी गई थी। यह मामला एक खंडपीठ के खंडित फैसले के बाद जस्टिस बहल के पास आया था, जिसमें जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस मनीषा आई मेहता शामिल थे। जस्टिस शर्मा ने अपील को स्वीकार कर लिया था, जबकि जस्टिस मेहता ने इसे खारिज कर दिया था। इसके बाद, मामले को तीसरे जज, जस्टिस बहल के पास भेजा गया, जिन्होंने अब जस्टिस शर्मा के मत से सहमति व्यक्त की है।

आईएमए ने 7 अगस्त को सेवाएं रोकने की चेतावनी दी थी, सरकार ने उठाया कदम

प्राइवेट अस्पतालों को मिली राहत, आयुष्मान का भुगतान शुरू, 500 करोड़ रुपये बकाया

हरिभूमि ब्यूरो चंडीगढ़

सरकार द्वारा प्राइवेट अस्पतालों का आयुष्मान कार्ड का बकाया भुगतान शुरू कर दिया है। इससे प्राइवेट अस्पतालों और आयुष्मान कार्ड धारकों को राहत मिली है। बता दें कि अस्पतालों का कुल 500 करोड़ रुपये बकाया है, जिसे सरकार ने पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर देना शुरू कर दिया है। हरियाणा की राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के अनुसार राज्य सरकार से 4 अगस्त, 2025 को बजट प्राप्त हो गया है। गौरतलब है कि अस्पतालों ने 7 अगस्त से आयुष्मान के तहत सेवाएं बंद करने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद सरकार हरकत में आई और भुगतान शुरू किया गया। राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के प्रवक्ता ने बताया कि भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए) द्वारा 28 जुलाई, 2025 को एक पत्र जारी किया गया था जिसमें आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बकाया भुगतानों का हवाला देते हुए 7 अगस्त से इस योजना के तहत सेवाओं को रोकने की बात कही गई थी। इस संदर्भ में,

अब तक 2900 करोड़ का भुगतान
हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने आई 2025 के पहले सप्ताह तक पैमलबद्ध अस्पतालों द्वारा प्रस्तुत दावों का निपटान और भुगतान कर दिया है। योजना की शुरुआत से अब तक अस्पतालों को कुल 2,900 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, 16 जुलाई 2025 तक राज्य और केंद्र सरकारों से 240.63 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हो चुकी है और पात्र दावों के निपटान के लिए इसका पूर्ण उपयोग किया जा चुका है।

50 डॉक्टरों की टीम करती है निपटान
पैमलबद्ध अस्पतालों द्वारा प्रस्तुत दावों का निपटान एनएसएफ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से 50 डॉक्टरों की एक टीम द्वारा किया जाता है। सभी कटौतियां एनएसएफ के दिशादेशों के अनुसार सख्ती से की जाती हैं और कटौती केवल तभी की जाती है जब पर्याप्त नैदानिक औचित्य या दस्तावेजीकरण का अभाव हो। किसी भी अस्वीकृत या कटौती से पहले, अस्पतालों को आवश्यक सहायक दस्तावेज जैसे कि वाइलड कार्ट, नैदानिक चित्र, ओटी नोट्स और परीक्षण रिपोर्ट अपलोड करने का अवसर दिया जाता है। यदि कोई अस्पताल किसी कटौती से असहमत है तो वह पौल के माध्यम से अपील दाखल कर सकता है। इन अपीलों की समीक्षा एक निरिद्ध चिकित्सा लेखा परीक्षा समिति द्वारा की जाती है।
एसएएच ने कहा है कि राज्य सरकार की तरफ से कल 4 अगस्त को बजट प्राप्त हो गया है और भुगतान शुरू कर दिया गया है।

400 से ज्यादा शिकायतें
एसएचए ने भुगतान में देरी, दावा अस्वीकृति और दावों का प्रसेंस्करण न करने संबंधी अस्पतालों द्वारा उठाई गई शिकायतों का संख्या भी ली है। अब तक पैमलबद्ध अस्पतालों की 400 से अधिक शिकायतों को औपचारिक रूप से सीजीआरएसएफ 2.0 पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत किया जा चुका है। इस प्लेटफॉर्म का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में अस्पतालों का समर्थन करने के प्रयास में, एसएचए ने अस्पताल प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किए हैं।

दस्तावेज जमा करें
अस्पतालों के पैमलमेंट और एनएसएफ प्रोत्साहनों के संबंध में वे हैं कि वे सभी अस्पताल जिन्होंने एनएसएफ प्रोत्साहन आवेदन प्रस्तुत किए थे और जिन्हें पूर्ववर्ती एचईएस 1.0 पोर्टल के माध्यम से अनुमोदन प्राप्त हुआ था, प्रोत्साहनों के लिए पात्र बने रहेंगे, बशर्तें उनके एनएसएफ प्रमाणपत्र वैध हों। एनएसएफ प्रोत्साहनों के लिए पात्र सिरों से आवेदन करने वाले अस्पतालों को एचईएस 2.0 पोर्टल के माध्यम से अद्यतन दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

सेवाएं जारी रखें
एसएचए, हरियाणा स्वास्थ्य सेवा वितरण में परादर्शिता, भुगतानों का समय पर वितरण और सार्वजनिक-निजी भागीदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। भुगतान की स्थिति और अन्य परिचालन संबंधी मामलों पर अपडेटेड हितधारकों से साझा किए जा रहे हैं। एसएचए हितधारकों से आग्रह करता है कि वे आयुष्मान योजना के तहत लोगों की स्वास्थ्य देखभाल को जल्द से जल्द पूरा करने में अपने सहयोगात्मक प्रयास जारी रखें।

अनुसूचित जाति के परिवारों को सूक्ष्म वित्त योजना के तहत मिलेगा लोन

हरिभूमि ब्यूरो चंडीगढ़
■ आगामी 21 अगस्त तक कर सकें हैं आवेदन
रुपये से कम है। वह ऋण के लिए आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, परिवार पहचान पत्र, पैन कार्ड व बैंक कॉपी पासपोर्ट साइज दो फोटो लेकर हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, से सम्पर्क कर सकते हैं या प्रार्थी hscfd.org.in साइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 21 अगस्त है।

धर्मांतरण पर कड़ी निगरानी, समारोह के लिए डीसी को देनी होगी सूचना

हरिभूमि ब्यूरो चंडीगढ़
इरादा रखने वाले किसी भी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन से पहले संबंधित उपायुक्त को प्रपत्र 'क' में एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिन मामलों में धर्मांतरण किया जाने वाला युवा नाबालिग है, वहां माता-पिता या जीवित माता-पिता दोनों को प्रपत्र 'ख' में एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, किसी भी धार्मिक पुजारी या धर्मांतरण समारोह का आयोजन करने वाले व्यक्ति को उस जिले के उपायुक्त को प्रपत्र 'ग' में पूर्व सूचना देनी होगी जहां धर्मांतरण की योजना है। ऐसी घोषणाएं या सूचनाएं प्राप्त होने पर, उपायुक्त एक रसीद जारी करके उनकी पावती देंगे, जिससे धर्मांतरण प्रक्रिया का औपचारिक दस्तावेज और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। इसके अलावा, सूचना प्रदर्शित होने के तीस दिनों की भीतर, कोई भी व्यक्ति उपायुक्त को आपत्ति दर्ज करा सकता है।

प्रवेश परीक्षा चूके छात्र की याचिका खारिज, 5 हजार का जुर्माना

पंचकूला। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक छात्र की याचिका को 'कानून में अनुचित' बताते हुए खारिज कर दिया है, जिसमें प्रवेश परीक्षा में शामिल न होने के बावजूद दाखिला देने की मांग की गई थी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस यशवीर सिंह राठौड़ की खंडपीठ ने कहा, यह प्रार्थना कानून में अनुचित है इसे मंजूर नहीं किया जा सकता। यह मामला चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय, हरियाणा में बीए एलएलबी (आनर्स) में प्रवेश पाने के इच्छुक एक छात्र से संबंधित था। छात्र ने याचिका में कहा कि प्रवेश परीक्षा पहले 2-3 जुलाई को निर्धारित थी, लेकिन बाद में स्थगित कर 16 जुलाई को की गई। जीए के नमन शर्मा दावा था कि वह नियमित आधिकारिक अपडेट की जांच कर रहा था। विश्वविद्यालय ने नई तारीख के संबंध में समय पर कोई एसएमएस, ईमेल या वेबसाइट पर नोटिस जारी नहीं किया, जिससे परीक्षा से चूक गया।

चीफ जस्टिस बोले- अगर कोई आम आदमी होता, तो छह महीने में जांच पूरी कर जेल भेज दिया गया होता
चीफ जस्टिस ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि लोग आप पर निगाह रखे हुए हैं, अगर यह कोई आम आदमी होता, तो छह महीने में जांच पूरी कर जेल भेज दिया गया होता। उन डीजीपी को वचुअली पेश होने को कहेंगे, ताकि वह स्वयं इसका स्पष्टीकरण दे सकें। वहीं हरियाणा सरकार के वकील ने विलंब का कारण बताते हुए कहा कि इनमें कुछ मामलों 5000 करोड़ रुपये के घोटाले से जुड़े हुए हैं। कोर्ट ने यह भी पाया कि पंजाब सरकार और चंडीगढ़ सरकार ने अभी तक कोई हलफनामा दायर नहीं किया है। इसके लिए अदालत ने दोनों को दो दिन का अतिरिक्त समय दिया है।

16 मुकदमों दर्ज, गृह सचिव हलफनामा दायर कर करें
कि इन मामलों में जांच अब तक पूरी क्यों नहीं हुई
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने बताया था कि हरियाणा में कुल 16 आपराधिक मुकदमों वर्तमान या पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित हैं, जिनमें एक मामला 2011 से, जबकि अन्य 2017, 2018 और 2019 से लंबित हैं। इस पर कोर्ट ने हरियाणा सरकार के गृह सचिव को निर्देश दिया था कि वे हलफनामा दायर कर स्पष्ट करें कि इन मामलों की जांच अब तक पूरी क्यों नहीं हुई।

वर्तमान या पूर्व सांसदों और विधायकों पर 13 मामलों लंबित हैं। इनमें से एक एफआईआर 2025 में दर्ज हुई थी, जिसमें चालान दाखिल किया जा चुका है, जबकि 11 में अब तक जांच जारी है।

पेड़ों पर कील ठोकने और लाइट लगाने पर याचिका, हाईकोर्ट ने प्रशासन से मांगा जवाब

पंचकूला। हरियाली और पेड़ों के संरक्षण को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा यूटी प्रशासन से जवाब तलब किया है। याचिका में हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के इलाकों में पेड़ों पर सजावटी कीलों, बिजली के तार और धातु की कीलों लगाने की अनियंत्रित और हानिकारक प्रथा पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है। इस याचिका पंचकूला निवासी मनमोहन सिंह एक पर्यावरण कार्यकर्ता ने दायर किया है। मामले की सुनवाई के दौरान याचिका के वकील मोहम्मद अरशद ने बेंच को बताया कि यह अमानवीय प्रथा पेड़ों को गंभीर परिस्थिति नुकसान पहुंचा रही है। इन सजावटी सामग्रियों और कीलों को लगाने से पेड़ों की छाल में गहरे घाव हो जाते हैं, जिससे वे थर्मल और यांत्रिक चोटों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं।
ये घाव फंगल संक्रमण और अन्य बीमारियों के प्रवेश द्वार बन जाते हैं, जो पेड़ों की को समय से पहले नष्ट कर देते हैं। याचिका में बताया गया कि यह केवल एक सौंदर्य संबंधी मुद्दा नहीं है, बल्कि यह पर्यावरण संतुलन के लिए खतरा है। इस तरह के कार्यों से न केवल वन्यजीव प्रजाति प्रभावित होते हैं, बल्कि पत्र तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने, आक्सीजन प्रदान करने और वायु प्रदूषण को कम करने में भूमिका निभाते हैं।

अभियुक्त की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा
धारा 82 CrPc देखिए
मेरे सम्बन्ध परिचायक किया गया है कि अभियुक्त लाल सिंह पुत्र ओमकार सिंह निवासी ग्राम-गोघ, थाना नारनोल, जिला महेंद्रगढ़ (हरियाणा) ने FIR No. 112/12, U/S 279/337/304A IPC, अन्तर्गत थाना नांगलोई, दिल्ली के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदिग्ध है कि उसने किया है) और उस पर जारी किया गए रिश्तापत्री के वारंट को यह लिखकर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त लाल सिंह मिल नहीं रहा है और मुझे समाधानप्रदा रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्त लाल सिंह फरार हो गया है (या उक्त वारंट के तामील से बचने के लिये अपने आपको छिपा रहा है)।
अतः इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि FIR No. 112/12, U/S 279/337/304A IPC, अन्तर्गत थाना नांगलोई, दिल्ली के उक्त अभियुक्त लाल सिंह से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के सम्बन्ध (या मेरे सम्बन्ध) उक्त परिचायक का उत्तर देने के लिए दिनांक 08.10.2025 को या इससे पहले हाजिर हो।
आदेशानुसार,
सुश्री विजयश्री राठीर
न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी - 10
परिषद, कमरा संख्या 345
तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली
DP/10346/OD/2025(Court Matter)

उत्तर रेलवे ई-निविदा सूचना
वर्कशॉप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर (आई/सी) उत्तर रेलवे, जगधारी वर्कशॉप, यमुनानगर, हरियाणा-135002, भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से, केवल निम्नलिखित कार्यों के लिए ऑनलाइन मोड के माध्यम से ई-निविदाएं आमंत्रित करता है:-
कार्य का नाम "स्टोर डिपो, जेयडीडब्ल्यू को नॉडल डिपो के रूप में विकसित करने के लिए प्रकाश व्यवस्था और वायरिंग व्यवस्था का प्रावधान।"
निविदा प्रकार **खुला** **बोली प्रणाली** **एकल पैकेट प्रणाली**
निविदा विक्रय तिथि 29.08.2025 प्रातः 11:30 बजे। निविदा अपलोड करने की तिथि 10.43 एवं समय
पूर्व-बोली आवश्यक है नहीं आज तक प्री-बिड क्लेरी ना
निविदा मूल्य रु. 65,32,007.63/- समी कर जीएसटी आदि सहित। निविदा अनुभाग टेंडर एवं वर्क्स/ इलेक्ट्रिकल शाखा जगधारी वर्कशॉप।
अग्रिम धन रु. 1,30,700/- ऑफर की वैधता 60 दिन
निविदा दस्तावेज लागत रु. N/A प्रलेख 2022 के भाग- 1 खंड संख्या 3 के अनुसार। सामान्य की अवधि 90 दिन
बोली आरंभ तिथि 15.08.2025 बोली समाप्ति तिथि 29.08.2025 प्रातः 11:30 बजे।
निविदा खोलने की तिथि एवं समय उसको बाद किसी भी समय निविदा को बंद किया जा सकता है। निविदाकर्ताओं को उद्घाटन के दौरान उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं है। निविदा बंद होने के बाद किसी भी समय निविदा खोलने का अधिकार रेलवे के पास सुरक्षित है।
वेबसाइट www.treps.gov.in पर जाएं
56/डब्ल्यू/इलेक्ट/ 25-26/टी/03/नॉडल डिपो 2373/2025
राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

हरियाणा सरकार निविदा सूचना
क्र. सं. दिनांक/ कार्य सूचना निविदा का नाम बुद्धि को प्रेषित करने की तिथि (सब) नॉडल/ईमेल (लाभ) वेबसाइट की वेबसाइट ई-मेल नोडल अधिकारी/सम्बंध विभाग/ ई-मेल
1 हैफेड हैफेड दाल मिल कॉम्प्लेक्स, हिसार में मौजूदा पुराने गोदाम, दाल मिल, एम. ऑफिस, चारदिवारी और अन्य ऋतिसर संरचना के विखण्डन के परचाय ई.आई. कार्य सहित 5000 एमटी क्षमता गोदाम (रूफिंग के बिना) का निर्माण, मैनेजर ऑफिस, सीसी रोड, लैचर हट, सेंट्रल टैंक और सॉलर पिट सहित शौचालय ब्लॉक, दाल मिल की चारदिवारी, कोलड स्टोरेज कॉम्प्लेक्स के गेट केबिन और सामने की चारदिवारी - 2 कार्य।
04.08.2025 9.19.25.138/-
18.08.2025 www.treps.gov.in haled@hry.nic.in
अधिक जानकारी हेतु कृपया पधारें : www.haryanaeprocurement.gov.in or www.etenders.hry.nic.in
संवाद-13/2026/60/37349/1/88/6 दि. 05.08.25

निदेश से मुलाकात, मांगों पर बनी सहमति एमपीएचडब्ल्यू का वेतन नियमित कर्मियों की तरह बढ़ाने के लिए फाइल दोबारा तैयार की जाएगी

हरिभूमि ब्यूरो चंडीगढ़

एमपीएचडब्ल्यू की मांगों को लेकर घंटों बातचीत और मंथन के बाद में सहमति बन गई है। निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से वार्ता में मांगों को लेकर सहमति बन गई है। बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कर्मचारी एसोसिएशन प्रतिनिधिमंडल राज्य प्रधान शर्मिला के नेतृत्व में सरकार के निमंत्रण पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन प्रशासनिक निदेशक डॉ. जितेंद्र कादियान से मिला। इस दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत महिला बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कर्मचारियों से संबंधित समस्याओं और मांगों का ब्योरा उनके सामने रखा गया। इस दौरान अधिकांश मांगों पर सहमति बनी और जल्द ही कार्यवाही का आश्वासन मिला। वेतनमान नियमित कर्मचारियों की भांति 35400 (4200 ग्रेड पे) के लिए दोबारा केवल एमपीएचडब्ल्यू (एफ) के वेतन संशोधन की फाइल दोबारा तैयार कर अनुमोदन के लिए वित्त विभाग को



■ ग्रेच्युटी की फाइल वित्त विभाग के पास है, जल्द मिलेगा लाभ
■ ड्रेस और एफटीए का लाभ अगले साल

भेजकर एसोसिएशन को सूचना दे दी जाएगी। ड्रेस और एफटीए के लिए इस वर्ष केंद्रीय मिशन निदेशक को पीपीपी मोड्यूल भेजकर अनुमति लेकर अगले वित्तवर्ष में लाभ प्रदान करने का आश्वासन दिया गया। इसके अलावा अन्य मांगों को लेकर एक मुश्त संवैधानिक लाभ के लिए ग्रेच्युटी की फाइल मुख्यमंत्री से अनुमोदित होकर बजट व्यवस्था के लिए वित्त विभाग में है, जल्द ही इस बारे में 100 प्रतिशत लाभ मिलेगा।

नगर निगम, रोहताक। PUBLIC NOTICE
Municipal Corporation, Rohtak
सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम से हतक के सुनारिया खर्द और सुनारिया कलां गाँवों में एक व्यापक जल निकासी व्यवस्था के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार की जानी है। एक सुदृढ़ और प्रभावी योजना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, हम सभी निवासियों, हितधारकों और आम जनता से बहुमूल्य सुझाव और प्रतिक्रिया आमंत्रित करते हैं। आपको राय जल भयव के प्रमुख क्षेत्रों को पहचान करने, सर्वान समझाने का प्रस्ताव करने और यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण है कि अंतिम योजना समुदाय की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करे। कृपया अपने सुझाव इस प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर मूल लिंक पर सुझाव दें।
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GFVWyyod1FJbfxLWHDppblPLMamVUnCoh_1RZaE3DYedit?usp=sharing
PL MamVUnCoh_1RZaE3DYedit?usp=sharing और यह मूल लिंक District Administration, Rohtak की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आपकी सक्रिय भागीदारी इस महत्वपूर्ण सार्वजनिक कार्य के सफल क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण योगदान देगी। किसी भी प्रश्न के लिए, आप नगर निगम, ये हतक को तकनीकी शाखा में सम्पर्क कर सकते हैं।
हस्ता/-कार्यकारी अधिकारता, नगर निगम, रोहताक।
संवाद 1078/11/790/2026/37325/IC/88/6 दि. 05.08.2025

कार्यालय पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय सोनीपत।
DD. NO. 40 दिनांक 02.08.2025 धारा 194 बी.एन. एस.एस. थाना खरखोटा जिला सोनीपत।
नाश की पहचान नाम-नामपता नामालुम पिता का नाम नामपता नामालुम पता-नामपता नामालुम उम्र-40 वर्ष कद-5 फुट 7 इंच।
हस्तिया: रंग सावंला लम्बूतरा चेहरा, काली आंखें काले बाल हैं।
पहननावा-बेगनी रंग की बनिधान जिसके उपर SAT URD AYS NYC-01 लिखा हुआ है कमर के काले रंग की लोवर पहने हुए हैं दाहिने हाथ की कलाई पर सूरमा से नरेंद्र गुदवाए हुए और लाल व पिले रंग का कलेवा बांधे हुए।
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 02.08.2025 को एक नामपता नामालुम नाम गौव हलालपुर खेतों से शीशम के पेड़ पर काले व स्लेटी रंग की को पेट जिस पर भूरे रंग की बेल्ट बंधी हुई है व पेट सफेद परना जिसमें काली व सफेद लाइन है से बंधा हुआ फिर परने से फंदा लगा कर हवा में लटकौ हुई नाश है। नाश को शिनाख हेतु डेड मोर्चरी हाउस सिलिल अस्पताल सोनीपत में रखवाया गया है। अगर किसी भी थाना/क्षेत्र से कोई गुमशुदगी हो या इस बारे कोई सुराग मिले तो निम्नलिखित नम्बरों पर सूचित करें।
प्रबन्धक थाना गन्नी मो नो-7419410542 अनुसंधान कर्ता तरुण संदीप नो 20 19/9 सोनोपत मो 0 नो - 9729342422 पुलिस कन्ट्रोल रूम सोनीपत- 0130-2222903
हस्ता/-अपराध अभिलेख अधिकारी कृते पुलिस उपायुक्त। मुख्यालय, सोनीपत।
पीआरडीएन-1084/11/3716/2026/37326/88/6 दि. 05.08.2025

हरियाणा लोक सेवा आयोग
बेज नं. 1-10, ब्लॉक-बी, सेक्टर-4, पंचकूला
घोषणा
विषय : विज्ञापन सं. 72 से 87 ऑफ 2024 के प्रत्युत्तर में उच्चतर शिक्षा विभाग (तकनीकी शिक्षा निदेशालय) में विभिन्न विषयों में लैक्चरर और फोरमैन इंस्ट्रक्टर के 237 पदों की भर्ती।
विज्ञापन सं. 72 से 87 ऑफ 2024 दिनांक 06.11.2024 और शुद्धिपत्र-1 दिनांक 03.02.2025 क्रमशः के प्रत्युत्तर में उच्चतर शिक्षा विभाग (तकनीकी शिक्षा निदेशालय) में विभिन्न विषयों में लैक्चरर और फोरमैन इंस्ट्रक्टर के पदों के लिए आवेदन कर चुके उम्मीदवारों की जानकारी हेतु एतद द्वारा यह घोषणा की जाती है कि घोषणा दिनांक 01.05.2025 के अनुरूप, आयोग ने विषय ज्ञान परीक्षा हेतु सभी विषयों का पाठ्यक्रम अधिसूचित कर दिया था। आगे आयोग ने निम्नलिखित पदों के लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट लेने का निर्णय लिया है।
क्र.सं. विज्ञा. सं. पद का नाम
01 75/24 सिविल इंजीनियरिंग में लैक्चरर
02 76/24 कंप्यूटर इंजीनियरिंग में लैक्चरर
03 77/24 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में लैक्चरर
04 80/24 मैकेनिकल इंजीनियरिंग में लैक्चरर
05 82/24 फार्मसी में लैक्चरर
06 84/24 फोरमैन इंस्ट्रक्टर
स्क्रीनिंग टेस्ट का पाठ्यक्रम निम्नानुसार है :-
स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए पाठ्यक्रम
सामान्य विज्ञान
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएँ
भारत का इतिहास
भारतीय और विषय भूगोल
भारतीय संस्कृति, भारतीय राजनीति और भारतीय अर्थव्यवस्था
सामान्य मानसिक योग्यता (संख्याएँ और उनके संबंध, क्रम और परिमाण इत्यादि - कक्षा 10 स्तर), आँकड़ा व्याख्या (चाटर्स, ग्राफर्स, तालिकाएँ, आँकड़ा पर्याप्तता आदि - कक्षा 10 स्तर)।
हरियाणा सामान्य ज्ञान - इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, संस्कृति आदि।
हस्ता/- उप सचिव
दिनांक : 05.08.2025 हरियाणा लोक सेवा आयोग
संवाद-1156/13/342/2026/37358/88/6 दि. 05.08.25 पंचकूला

धान पर फिजी वायरस का कहर, 70% तक बर्बाद, किसान ने फसल पर चलाया ट्रैक्टर

■ सैकड़ों एकड़ फसल को चट कर गया वायरस ■ किसानों ने सरकार से मुआवजे की लगाई गुहार

राजपाल जिंदल ► गुहला वीका

हरियाणा-पंजाब सीमा से सटे गांवों में इस बार धान की फसल पर फिजी वायरस का भारी असर देखने को मिल रहा है। बीमारी के चलते किसानों की कई एकड़ खड़ी फसल पूरी तरह से खराब हो गई है। हालात इतने खराब

हो चुके हैं कि कुछ किसानों ने अपनी बर्बाद फसल को खेत में पलट दिया है, ताकि दोबारा नई फसल बोई जा सके। गांव दाबा चाबा के किसान प्रताप सिंह, निशान सिंह, महल सिंह, जसविंदर सिंह, बुटा सिंह, बलिहार सिंह और गुरदीप सिंह ने पत्रकारों को बताया कि इस बार अज्ञात बीमारी ने क्षेत्र की 50% से 75% तक धान की फसल को अपनी चपेट में ले लिया है। इससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। एक किसान ने बताया कि उसने अपनी 8



गुहला वीका। खराब धान फसल दिखाते किसान।

एकड़ की बीमार फसल को नष्ट कर दिया है और अब वह दोबारा फसल की तैयारी में जुटा है।

किसानों की उड़ी नींद

बता दें कि इस बीमारी के कारण किसानों की गाढ़े पसीने की कमाई नष्ट हो रही है। किसानों ने प्रति एकड़ करीब 30 हजार रुपये खर्च पर अपनी धान की फसल तैयार की थी लेकिन फिजी

वायरस के कारण उनकी तैयारी की गई फसल नष्ट हो गई है। किसानों ने बताया कि करीब दो महीने पहले धान की बुवाई की गई थी और उन्होंने खाद, कीटनाशक दवाइयों और अन्य जरूरी चीजों पर भारी खर्च किया था। लेकिन अब बीमारी की वजह से उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया है। घग्गर क्षेत्र के किसानों ने सरकार से मांग की है कि तुरंत टीम भेजकर जांच करवाई जाए।



गुहला वीका। धान की फसल पर ट्रैक्टर चलाता किसान।

फसल में फिजी वायरस का प्रकोप : उप निदेशक

कृषि उप निदेशक कैथल डा. बाबू लाल ने बताया कि इस समय धान की फसल में फिजी वायरस का प्रकोप है। यदि शुरूआती दौर में इस वायरस पर स्प्रे न किया जाए तो यह अधिक पैमाने पर होकर धान की फसल को पैदावार को रोक देता है। इस कारण पोधा सूखने के कारण पर पहुंच जाता है। समय पर दवाई के स्प्रे से इस पर काबू पाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 में भी इस वायरस का प्रकोप देखा गया था। इसे लेकर बुधवार को कैथल में कृषि विज्ञानियों का एक शिष्टमंडल भी पहुंच रहा है। इससे नष्ट हुई फसल का सर्वे करके हुए रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजी जाएगी।

एमटीपी नियमों के उल्लंघन पर चार अस्पतालों के दो से चार माह के लिए गर्भपात लाइसेंस रद्द

हरिभूमि न्यूज ► जींद

मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी (एमटीपी) नियमों की अवहेलना कर स्वास्थ्य विभाग ने सख्त दिखाई है। पिछले दिनों सीएमओ के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने निजी अस्पतालों को जांचने का काम किया था। इस जांच में कई अस्पतालों में नियमों की अवहेलना मिली थी। जिसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई थी। बाकायदा शहर के एक अस्पताल पर स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी भी की थी। अब स्वास्थ्य विभाग ने चार निजी अस्पतालों के लाइसेंस रद्द करने का निर्णय लिया है। इनमें जींद के दो निजी अस्पतालों का गर्भपात लाइसेंस दो माह के लिए, सफीदों के एक निजी अस्पताल का गर्भपात केंद्र का लाइसेंस दो माह के लिए तथा शशि शर्मा अस्पताल का लाइसेंस चार माह के लिए रद्द किया गया है।

अस्पतालों में मिली खामियां

जून माह में नागरिक अस्पताल में सीएमओ डा. सुमन कोहली की अध्यक्षता में जिलास्तरीय एमटीपी कमेटी की बैठक हुई थी। इस बैठक में एमटीपी निरीक्षण टीम द्वारा प्राइवेट अस्पतालों की निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। प्रस्तुत रिपोर्ट में बताया गया था कि निरीक्षण के दौरान जिला जींद के तीन प्राइवेट अस्पतालों में एमटीपी नियमों के तहत कमियां पाई गई हैं। वहीं

सख्त कार्रवाई करेंगे : सीएमओ



एमटीपी नियमों की अवहेलना किसी भी स्तर में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन्होंने नियमों की अवहेलना पर चार अस्पतालों पर कार्रवाई की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रत्येक अस्पताल एमटीपी नियमों के तहत अपना रजिस्टर, रिकॉर्ड, स्टॉक को अपडेट रखें। लेबर रूम में साफ-सफाई पर विशेष ध्यान रखते हुए बायो मेडिकल वेस्ट अनुज्ञार वेस्ट को मैनेज करें। अगर नियमों की अवहेलना होती है तो सख्त विभागीय कार्रवाई में लाई जाएगी।

सफीदों के एक अस्पताल में भी कमी मिली थी। एमटीपी नियमों अनुसार यह जरूरी है कि अस्पताल के लेबर रूम में हाइजीन (साफ-सफाई) का होना बहुत जरूरी है।

इन्फेक्शन का खतरा

निरीक्षण दौरान यह पाया गया कि इन अस्पतालों में बायो मेडिकल वेस्ट नियमों के तहत प्रबंध नहीं है। लेबर रूम में पहले से प्रयोग किए गए हाथ में पहने जाने वाले ग्लव, प्रयोग की गई वॉयल, कुछ जंग लगे मेडिकल औजार लेबर रूम में मौजूद थे। जिससे मरीज को इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। अस्पताल के एडमिशन रजिस्टर व एमटीपी स्टॉक रजिस्टर में भी कमियां पाई गई थी।

पूर्व सीएम भजनलाल के भतीजे की गाड़ी पर हमला, जांच में जुटी पुलिस

फतेहाबाद। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के भतीजे और फतेहाबाद के पूर्व विधायक दुडाराम के भाई उग्रसेन की गाड़ी पर सोमवार देर रात अज्ञात हमलावरों द्वारा लाठी-डंडों से हमला करने का मामला सामने आया है।

देर रात करीब 11 बजे दो गाड़ियों में आए 4-5 लोगों ने गांव झलनियां-मोहम्मदपुर रोही रोड पर उनकी गाड़ी को रूकवाया और उस पर हमला बोल दिया। बताया जाता है कि घटना के बाद उग्रसेन अपने पैतृक गांव मोहम्मदपुर रोही से वापस फतेहाबाद लौट रहे थे और गाड़ी को चालक सुशील कुमार चला रहा था। इस हमले में किसी को गंभीर चोटें नहीं आई हैं वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई और इाईवर सुशील की शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। बताया गया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान दुडाराम के भाई व गांव के ही



जल्द गिरफ्तार करेंगे

इस मामले में पुलिस अधीक्षक रिश्तत जैन ने कहा कि पूर्व विधायक दुडाराम के भाई की गाड़ी पर हुए हमले और तोड़फोड़ मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों की पहचान कर ली गई है। सी.आई.डी. सहित पुलिस की तीन टीमों डीएसपी के नेतृत्व में रात से ही हमलावरों की तलाश में जुटी है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

कृपाराम नाम के व्यक्ति की आपसी बहस हो गई थी। बाद में कृपाराम पर गंभीर धाराओं के तहत केस भी दर्ज हुआ था। कुछ लोग इस मामले को इसी विवाद से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है।

जींद में 15 हजार लेता कर्मचारी पकड़ा

जींद। एंटी कर्प्शन ब्यूरो की टीम ने मंगलवार शाम को बिजली निगम का कर्मियों बन ठेकेदार के कारिंदे को बिजली मीटर लगाने की एवज में 15 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों काबू किया है। गांव इंटलकाना निवासी राजेश ने एंटी कर्प्शन ब्यूरो को दी शिकायत में बताया था कि उसके श्याम नगर में दो मकान हैं। उसने काफी समय पहले बिजली निगम में बिजली मीटर लगाने के लिए आवेदन किया था। खुद को बिजली निगम का कर्मियों बताते वाला पवन सैनी बिजली मीटर लगाने के लिए 15 हजार रुपये रिश्वत की मांग कर रहा है। शिकायत के आधार एसीबी के निरीक्षक दिनेश कुमार के नेतृत्व में छापामार टीम का गठन किया गया। जबकि निर्माण विभाग के एचडीओ दीपक नेन को राजपत्रित अधिकारी नियुक्त किया गया। छापामार टीम ने शिकायतकर्ता को 30 नोट 500-500 के पाउडर तथा हस्ताक्षर थमा दिए। संपर्क साधने पर पवन सैनी ने शिकायतकर्ता को न्यू सब्जी मंडी के निकट बुला लिया। शिकायतकर्ता ने पवन सैनी को रिश्वत राशि थमाने के साथ छापामार टीम ने काबू कर लिया और उसके कब्जे से रिश्वत राशि को बरामद कर लिया।

रेवाड़ी में पटवारी व पानीपत में वलर्क रिश्वत लेते काबू



10 हजार ले रहा था

पानीपत। एंटी कर्प्शन ब्यूरो ने लघु सचिवालय के एसडीएम कार्यालय के आरसी वलर्क रिकू जागलान को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपी तीन बाइकों की लोन फ्री आरसी बनाने के बदले में रुपए देने की डिमांड कर रहा था। उसकी शिकायत मिलने के बाद एंटी कर्प्शन ब्यूरो की टीम ने उसे दैप लगाकर पकड़ लिया। आरोपी रिकू कुमार आरसी से लोन हटाने और एक अन्य बाइक की आरसी ट्रान्सफर संबंधित तीन फाइल पास करने की एवज में 9 हजार प्रति फाइल के हिसाब से 27 हजार रुपए की रिश्वत मांग रहा था।

पहले उसने पटवारी को 9 हजार रुपये दे दिए थे। शेष 11 हजार रुपये मंगलवार को देने की बात कही थी। इसी दौरान सुरेंद्र ने एसीबी के अधिकारियों से रिश्वत मांगने की शिकायत की। एसीबी की टीम ने एक योजना के अनुसार सुरेंद्र को पाउडर लगे हुए 11 हजार रुपये के नोट देकर पटवारी के पास भेज दिया। जैसे ही सुरेंद्र ने पटवारी को रकम देकर टीम को इशारा किया, एसीबी की टीम ने उसे मौके पर ही काबू कर लिया।

हरियाणा सरकार

“ पीएम आवास योजना से लोगों को न सिर्फ पक्का घर मिल रहा है, बल्कि इससे गांवों और शहरों में रोजगार के भी अनेक अवसर बन रहे हैं। ”

- नरेन्द्र मोदी

हरियाणा सरकार का है सपना, सबका घर हो अपना

मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना

मुख्य बिन्दु

- पारिवारिक वार्षिक आय ₹1.80 लाख
- घुमन्तु जाति के परिवारों को प्राथमिकता
- 1 मरला (30 वर्ग गज) प्लॉट मात्र ₹1 लाख में

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अन्तर्गत मकान निर्माण हेतु ₹2.5 लाख की सब्सिडी का प्रावधान

वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन पारदर्शी प्रक्रिया

बुकिंग

सभी साइट्स के नक्शे उपलब्ध

सरल बुकिंग भुगतान विकल्प

निम्न 16 शहरों में 15,251 प्लॉटों का प्रावधान

• चरखी-दादरी	• हिसार
• सिरसा	• झज्जर
• फतेहाबाद	• जगाधरी
• सफीदों	• अम्बाला
• रोहतक	• रेवाड़ी
• महेन्द्रगढ़	• करनाल
• पलवल	• जुलाना
• बहादुरगढ़	• जीन्द

न्यूनतम बुकिंग राशि मात्र 10,000 रुपये बुकिंग की अंतिम तिथि 15.08.2025

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें

कॉल करें 0172-2585852 अथवा पोर्टल www.hfa.haryana.gov.in पर जाएं

हाउसिंग फॉर ऑल विभाग, हरियाणा

सूचना, लोक संपर्क तथा भाषा विभाग, हरियाणा www.prharyana.gov.in | Follow us on

विपक्ष अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने में माहिर : पीएम मोदी

एजेसी नई दिल्ली

दिल्ली स्थित संसद भवन परिसर में मंगलवार को एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई। इसमें एनडीए सांसदों ने ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव की सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री को हार पहनाया। सांसदों ने 'हर-हर महादेव', 'भारत माता की जय' के नारे लगाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने सांसदों को अपने संबोधन में कहा, 'संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग करके विपक्ष ने गलती की। इसमें उनकी ही फजीहत हुई। विपक्ष अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने में माहिर है। विपक्ष रोज ऐसी चर्चा कराए, हम इस फ्रीड में माहिर हैं।' प्रधानमंत्री ने कहा, 'बिहार में वोटर्स लिस्ट रिविजन के मुद्दे पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। देश की जनता सब देख रही है।' प्रधानमंत्री ने अमित शाह की भी तारीफ की और कहा कि वे अब सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले केंद्रीय गृह मंत्री हैं।

ऑपरेशन सिंदूर पर बहस की मांग करके गलती की

एनडीए सांसदों ने पीएम को सम्मानित किया



सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित : एनडीए सांसदों की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव भी पास किया गया। इसमें कहा गया कि सैन्य शक्ति और मजबूत नेतृत्व के जरिए इंसाफ हुआ। भारत आतंकवाद को न तो भूलता है और न ही कभी माफ करता है।

एक साल बाद हुई बैठक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सतारुद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के सांसदों को मंगलवार को करीब एक साल से अधिक समय के अंतराल के बाद संबोधित करते हुए एक स्वाभाविक और जैविक गठबंधन के रूप में सामूहिक पहचान स्थापित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि 1998 में राजग की स्थापना के बाद से इसकी यात्रा सफलताओं से भरी हुई है तथा इसमें और भी कई उपलब्धियां हैं। मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और उसके सहयोगी दलों के सदस्यों को सतारुद गठबंधन के हिस्से के रूप में विभिन्न क्षेत्रों में अपनी-अपनी ताकत से परे जाकर विभिन्न कार्यक्रमों में बंद-चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। राजग के संसदीय दल की पिछली बैठक दो जुलाई, 2024 को हुई थी।

खबर संक्षेप

फिल्म 'खालिद का शिवाजी' को बैन करे

मुंबई। स्थानीय हिंदू संगठन ने मराठी फिल्म 'खालिद का शिवाजी' पर आपत्ति जताते हुए सेंसर बोर्ड के पास बैन करने की मांग की है। ये फिल्म 8 अगस्त को रिलीज होने वाली है। इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास को गलत तरीके से पेश करने का आरोप है।

साउथ एक्टर बलराज का 34 साल में निधन

चेन्नई। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के कलाभवन नवास, सुपरस्टार प्रेम नजीर के बेटे और अभिनेता शानवास के बाद अब कन्नड़ अभिनेता संतोष बलराज के निधन की खबर है। कन्नड़ अभिनेता संतोष बलराज का 34 साल की उम्र में एक निजी अस्पताल में निधन हो गया।

लड़की ने 50 घंटे घोड़े पर सवारी कर तोड़ा रिकॉर्ड

जयपुर। जयपुर की मान्या शक्तावत ने 50 घंटे तक बिना रुके घोड़े पर सवारी कर युवा पीढ़ी को प्रेरित किया है। 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है, 22 जुलाई की सुबह 4:20 बजे मान्या ने चुनौती की शुरुआत की और 50 घंटे तक घुड़सवारी की।

ईडी के समक्ष पेश हुए उद्योगपति अनिल अंबानी

नई दिल्ली। उद्योगपति अनिल अंबानी मंगलवार को दिल्ली में ईडी के सामने पेश हुए। रिलायंस ग्रुप की कंपनियों से जुड़े 17,000 करोड़ रुपये के कथित बैंक लोन घोटाले के मामले में केंद्रीय एजेंसी ने अंबानी को पूछताछ के लिए बुलाया था। अनिल अंबानी को पिछले हफ्ते समन भेजा गया था। ईडी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। जांच के दायरे में रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस कम्युनिकेशंस जैसी कंपनियां हैं।

केंद्रीय सचिवालय के पहले आधुनिक भवन का आज उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी

नई दिल्ली (ब्यूरो)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को राजधानी दिल्ली में कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन करेंगे। यह भवन केंद्र सरकार की बहुप्रतीक्षित 'साक्षात् केंद्रीय सचिवालय परियोजना का पहला प्रमुख हिस्सा है। उद्घाटन समारोह सुबह 12:15 बजे निर्धारित है। कर्तव्य भवन 3 के उद्घाटन के साथ ही केंद्र सरकार के कई मंत्रालयों और विभागों को अब पुराने भवनों से स्थानांतरित किया जाएगा। इसे नवीन भारत के प्रशासनिक ढांचे का पहला मील का पथर माना जा रहा है। यह भवन करीब 1.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें वाउड सहित छह मंजिलें और दो अतिरिक्त तल शामिल हैं। गृह मंत्रालय, खासगी विकास, पेट्रोलियम, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, कार्मिक मंत्रालयों सहित कई विभागों के लिए कार्यालय कक्ष बनाए गए हैं।

हंगामे के बीच लोकसभा में ध्वनि मत से विधेयक पारित

गोवा विस में एसटी के लिए सीट आरक्षित करने के प्रावधान वाले विधेयक को मंजूरी

एजेसी नई दिल्ली

लोकसभा ने मंगलवार को 'गोवा राज्य, सभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक, 2024' विधेयक को पारित कर दिया जिसमें गोवा विधानसभा में एसटी समुदाय के लिए सीट आरक्षित करने का प्रावधान है। सदन ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के बीच ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी प्रदान की। इसे पिछले साल पांच अगस्त को निचले सदन में प्रस्तुत किया गया था और दिसंबर में संसद के शीतकालीन सत्र में इस पर चर्चा हुई थी। एसआईआर के मुद्दे पर लोकसभा की बैठक सुबह एक बार स्थगित होने के बाद दो बजे शुरू हुई तो पीठासीन सभापति संजया राय ने विधेयक को पारित करने के लिए प्रस्तुत करने के वास्ते कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का नाम पुकारा।



बिल को पास करने का उद्देश्य

बिल का मकसद इस असमानता को दूर करना है ताकि एसटी समुदाय को भी संविधान में दिए गए आरक्षण का लाभ मिल सके। यह बिल पिछले साल यानी 6 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन अब जाकर पारित हुआ है। यह संसद के मौजूदा मानसून सत्र में लोकसभा द्वारा पारित किया गया पहला बिल है। बिल पास होने के बाद संसद की कार्यवाही दिग्भ्रम के लिए स्थगित कर दी गई।

सीआईएसएफ की मौजूदगी पर तक्रार

सदन में सीआईएसएफ कर्मियों की मौजूदगी के मुद्दे पर राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। सभापति ने आपत्ति जताई कि जब खरगे ने उन्हें सीआईएसएफ कर्मियों की तैनाती को लेकर पत्र लिखा था तो उसे मीडिया में क्यों जारी किया गया? खरगे ने कहा कि उन्होंने इसे लेकर मीडिया में बयान जारी किया। चर्चा के दौरान जेपी नड्डा ने विपक्ष के रवैए पर सवाल उठाए और नसीहत देते हुए कहा कि विपक्ष को उनके दृष्टिकोण लेने की जरूरत है।

उड़ानों में हंगामा, 48 यात्री 'नो-फ्लाई लिस्ट' में

मंगलवार को केंद्र सरकार ने बताया कि इस साल 30 जुलाई तक 48 यात्रियों को 'नो-फ्लाई लिस्ट' में डाला गया है। यानी अब ये यात्री किसी विमान में सफर नहीं कर सकते। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोले ने राज्यसभा में यह जानकारी दी। पिछले कुछ वर्षों में भी बड़ी संख्या में ऐसे यात्रियों को इस लिस्ट में डाला गया था, जहां 2024 में 82 और 2023 में 110 यात्रियों पर प्रतिबंध लगाया गया। यह कर्वाईड विमान में अनुशासनहीन या हिंसक व्यवहार के कारण की जाती है। डीजैसीएफ के नियमों के मुताबिक, तीन सत्र पर यात्रियों की बंदसलूकी को वर्गीकृत किया जाता है। इसमें लेवल कुछ प्रकार है कि लेवल एक में हल्का व्यवहार, जैसे जोर-जोर से बोलना। इसके लिए तीन महीने के लिए प्रतिबंध लगाया जाता है। वहीं दूसरे लेवल में शारीरिक या अपमानजनक व्यवहार। इसके तहत छह महीने के लिए प्रतिबंध लगाया जाता है।

नड्डा बोले- कार्यवाही को बाधित करना अलोकतांत्रिक

खरगे के बयान पर नड्डा ने कहा कि 'कार्यवाही को बाधित करना अलोकतांत्रिक है और यह नियमों के खिलाफ है। जिन घटनाओं का उपसमापन में उल्लेख किया कि किस तरह से स्पीकर को बोलते समय बाधित किया गया, तो यह लोकतंत्र नहीं है। मैं 40 साल से ज्यादा विपक्ष में रहा हूँ, मुझे दृष्टान्त नहीं मिले। अभी आपको 10 ही साल हुए हैं, अभी 30-40 साल और विपक्ष में ही रहना है।

'नेता' और 'नेता प्रतिपक्ष' में टेंशन, नड्डा बोले- खरगे लें मुझसे ट्यूशन

खरगे ने पूछा- क्या हम आतंकवादी हैं?

खरगे ने कहा कि जब सदन के नेता अहम मुद्दे उठा रहे होते हैं तो उस समय सदन में सीआईएसएफ कर्मियों की तैनाती गलत है। उन्होंने अरुण जेटली और सुभाष चव्वाला का उद्धरण दिया। खरगे ने कहा कि ऐसे में अगर मैंने आपको पत्र लिखा और उस बारे में मीडिया में जानकारी दी गई तो उस पर आपको इतनी आपत्ति क्यों है? मैं सभी सदस्यों को सूचित नहीं कर सकता, इसलिए एक प्रस नोट जारी किया। मुझे बताइए सीआईएसएफ की वेल में तैनात क्यों किया गया? क्या हम आतंकवादी हैं?

आर्टिकल 370 निरस्त करने की छठी वर्षगांठ

दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी कड़ी पीढ़ियों ने झेला है आतंक का दंश : एजली

एजेसी श्रीनगर

आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाएं



उपराज्यपाल ने कहा कि मैं शर्हीद हुए नागरिकों के परिजनों को आश्वस्त करता हूँ कि जब तक आतंकवादियों के अत्याचारों का शिकार हुए हर परिवार को न्याय नहीं मिल जाता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा।

पुनर्वास के लिए प्रयास करेंगे

मनोज सिन्हा ने कहा कि आतंकवाद पीड़ित परिवारों के लिए न्याय और राहत की लंबी प्रतीक्षा समाप्त हुई। हम आतंकवाद पीड़ितों के पुनर्वास के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आतंकवाद पीड़ित परिवारों के रिश्तेदारों से मेरा वादा है कि इस जटिल अपराध के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी।

उमर ने पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर राजनीतिक दलों के प्रमुखों को लिखा पत्र

श्रीनगर (भाषा)। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को 40 से अधिक राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को पत्र लिखकर इस केंद्रशासित प्रदेश के पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कराने के लिए उनका समर्थन मांगा और कहा कि इसे शक रियायत के रूप में नहीं, बल्कि एक आवश्यक सुधार के रूप में देखा जाना चाहिए। अधिकारियों के अनुसार, अब्दुल्ला ने अपने दो पन्नों के पत्र में मौजूदा संसद सत्र के दौरान जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए एक विधेयक लाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री की यह अपील जनकी सरकार द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा तत्काल बहाल करने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित करने के नौ महीने बाद आई है। उनका कहना है कि प्रस्ताव को व्यापक रूप से प्रमाणित करने का सौंपा गया था। यह पत्र जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करने और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों - लद्दाख और जम्मू-कश्मीर - में विभाजित करने की छठी वर्षगांठ पर आया है।

राहुल को फटकार पर भड़की प्रियंका सुप्रीम कोर्ट के जज तय नहीं कर सकते कि सच्चा भारतीय कौन?

विपक्ष के नेता का काम है सरकार से सवाल पूछना

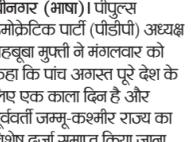
एजेसी नई दिल्ली

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड़ा ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर अपने भाई राहुल गांधी का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज यह तय नहीं कर सकते कि कौन सच्चा भारतीय है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर राहुल सच्चे भारतीय हैं, तो उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। चीनी कब्जे पर

राहुल ने यह गलत बयान दिया था। प्रियंका गांधी ने कहा कि विपक्ष के नेता का काम होता है सरकार से सवाल पूछना और उसे चुनौती देना। उन्होंने कहा कि राहुल सना का हमेशा सम्मान करते हैं। उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। वहीं, इस मामले को लेकर भाजपा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने चीन को मजबूत करने की कसम खाई है।

पांच अगस्त पूरे देश के लिए 'काला दिन' : महबूबा मुफ्ती

श्रीनगर (भाषा)। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने मंगलवार को कहा कि पांच अगस्त पूरे देश के लिए एक काला दिन है और पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त किया जाना



देश के संवैधानिक मूल्यों पर एक व्यापक हमले की शुरुआत थी। पीडीपी ने यह भी दावा किया कि पांच अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को एकपक्षीय और असंवैधानिक तरीके से निरस्त किए जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन से पार्टी की अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं को पीडीपी कार्यालय से बाहर निकलने से रोका गया। महबूबा ने सोशल मीडिया में 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, पांच अगस्त न केवल जम्मू-कश्मीर के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए एक काला दिन है। इस दिन, संविधान को विदेशी ताकतों ने नहीं, बल्कि हमारे लोकतंत्र के केंद्र में कूर बहुमत द्वारा विकृत किया गया था।

जिन्दल स्टील लिमिटेड

(पूर्व में जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के रूप में जानी जाती)
(CIN: L27105HR1979PLC000913)

पंजी. कार्यालय : ओ.पी. जिन्दल मार्ग, हिसार-125005 (हरियाणा)
कॉर्पोरेट सचिवालय कार्यालय : जिन्दल सेंटर, टावर-ए, द्वितीय तल, प्लॉट नं. 2, सेक्टर-32, गुडगांव-122001 (हरियाणा)
Website: www.jindalsteel.com | Email: investorcare@jindalsteel.com | Tel.: +91 124 6612000

फिजिकल शेयरों के हस्तांतरण आगमन के पुनः प्रवृत्तीकरण हेतु स्पेशल विंडो

सेबी सर्कुलर नं. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-POD/PI/CIR/2025/97 दिनांक 02 जुलाई, 2025 के अनुसार, जिन शेयरधारकों ने 1 अप्रैल, 2019 को समय सीमा से पहले अपने फिजिकल शेयरों के ट्रांसफर ड्राइव प्रस्तुत किए थे और जिन्हें दस्तावेजी/प्रक्रिया में कमी या अन्य कारणों से अस्वीकार/वापस कर दिया गया और जो अपना आग्रह पुनः प्रस्तुत करने से चूक गए, उन्हें नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करके हस्तांतरण आग्रह पुनः प्रस्तुत करने का एक और अवसर दिया गया है :

हस्तांतरण आगमन के पुनः प्रवृत्तीकरण हेतु विंडो	7 जुलाई, 2025 से 6 जनवरी, 2026 तक।
हस्तांतरण आगमन के पुनः प्रवृत्त कर सकता है	निवेशक विनोद ट्रांसफर ड्राइव अप्रैल 2019 से पहले प्रस्तुत किए गए थे और दस्तावेजों में कमी के कारण अस्वीकार/वापस कर दिया गया था।
पुनः प्रवृत्तीकरण हेतु प्रक्रिया	मूल हस्तांतरण दस्तावेज, सही या छूटे हुए विवरणों के साथ, हमारे रजिस्ट्रार एच.एस.ए. ट्रांसफर सेंटर ("आरटीसी") को नीचे दिए गए पते पर जमा करें : अनंकित अग्रिम/सेल लिमिटेड 4ई/2 इंडियावाला एक्सप्रेसवे, नई दिल्ली-110055 ईमेल - ramap@anankit.com द्वारा फोन नंबर - 011-42541955

इस अवधि के दौरान, प्रतिभूतियों को हस्तांतरण के लिए पुनः प्रस्तुत की जाती है, केवल डीमैट/रियल/इ-ड्राइव रूप में जारी की जाएंगी। इस स्पेशल विंडो के खुलने से संबंधित विवरण कंपनी की वेबसाइट www.jindalsteel.com पर भी प्रचारित किया गया है।

कुने जिन्दल स्टील लिमिटेड
(पूर्व में जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के रूप में जानी जाती)

हस्ता./-
दाभोदर भिल्ल
पुर्णकालिक निदेशक
डीआईएन : 00171650

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 5 अगस्त, 2025

क्र. सं.	विभाग का नाम	कार्य सूचना निविदा का नाम	खुलने की तिथि	राशि/ईएमडी (लाभभा) रु. में	विभाग की वेबसाइट	मोडल अधिकारी / सम्यक विवरण/ई-मेल
1	महानिदेशक आपूर्ति एवं निपटान पंचकुला हरियाणा	स्टोर का वर्णन :- क्र. सं. 01 से 19 मर्च तक मर्चें निहित सूची (19 मर्चों का सिंगल लॉट)।	06.08.2025	12.52 लाख	https://etenders.hry.nic.in/dsndharyana.gov.in	0172-2570122 Supplies@hry.nic.in
2	महानिदेशक आपूर्ति एवं निपटान पंचकुला हरियाणा	स्टोर का वर्णन :- क्र. सं. 01 से 34 मर्चों तक मर्चें निहित सूची (34 मर्चों का सिंगल लॉट)।	06.08.2025	12.52 लाख	https://etenders.hry.nic.in/dsndharyana.gov.in	0172-2570122 Supplies@hry.nic.in
3	महानिदेशक आपूर्ति एवं निपटान पंचकुला हरियाणा	स्टोर का वर्णन :- क्र. सं. 01 से 05 मर्चों तक मर्चें निहित सूची (05 मर्चों का सिंगल लॉट)।	06.08.2025	12.52 लाख	https://etenders.hry.nic.in/dsndharyana.gov.in	0172-2570122 Supplies@hry.nic.in
4	पंचायती राज रोहतक	लाहौत में एडब्ल्यूसी का निर्माण, जैडपी।	01.08.2025	9215555586	https://etenders.hry.nic.in	9215555586 sdoprohakt134@gmail.com
5	पंचायती राज कैथल	गांव चंदाना, ब्लॉक कैथल में एसएचसी का निर्माण।	01.08.2025	46.66 लाख	https://etenders.hry.nic.in	1746234748 prexeeng.Kti@hry.nic.in
6	पंचायती राज कलानीर	गांव खेरडी, ब्लॉक कलानीर जिला रोहतक में ओबीसी चौपाल को पूरा करना।	07.08.2025	18.08.2025	https://etenders.hry.nic.in	7015118527 sdokalanour@gmail.com
7	पंचायती राज गनीर	गांव पट्टी ब्राह्मणा में शैड (शमशान घाट में बरामदा) का निर्माण, स्कीम का नाम डी प्लान 2025-26, ब्लॉक गनीर हिडौलीन का नाम सोनीपत।	01.08.2025	5.80 लाख	https://etenders.hry.nic.in	7015771521 sdoprganaur1@gmail.com
8	बी.पी.एस. राजकीय महिला शिक्षा महाविद्यालय खानपुर कलां, सोनीपत	बीपीएस जीएमसी (डब्ल्यू) खानपुर कलां सोनीपत में परेस्ट कंट्रोल सर्विसेज के लिए ई-निविदा + चार कार्य।	05.08.2025	2.11 लाख	https://etenders.hry.nic.in	9416803361 Bpsmc.purchase@gmail.com
9	सिविल सर्जन, जौन्द	जिला जौन्द में औषधियों और अन्य मर्चों की खरीद के लिए ई-निविदा सूचना का प्रकाशन।	02.08.2025	2 लाख	https://etenders.hry.nic.in	7015444191 cds_jind@gmail.com
10	नियंत्रक मद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हरियाणा, पंचकुला	प्रेस सामग्री की खरीद।	06.08.2025	11 लाख	https://etenders.hry.nic.in	9872020766 printing@hry.nic.in

अधिक जानकारी हेतु कृपया पधारें : www.etenders.hry.nic.in

पीआरडी/घ-11/2026/200/37373/1/88/6 दि. 05.08.25

चिंतन

यूएस खुद रूस से कर रहा ट्रेड, अपने हित देखे भारत

भारत को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकियों व चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। इसका कारण है कि एक तो खुद अमेरिका दोहरा मानदंड अपना रहा है, दूसरा भारत को अपने राष्ट्रीय हित की रक्षा करने का हक है। भारतीय निर्यात पर ट्रंप जितना भी शुल्क लगाए, उसका अमेरिकी जनता को ही खामियाजा भुगतना होगा। फ़ैरी तौर पर हो सकता है कि भारत से अमेरिका को होने वाले निर्यात में कमी आए, लेकिन इससे भारत को विचलित होने की जरूरत नहीं है। इसे भारत को एक अवसर के रूप में लेना चाहिए और भारतीय निर्यातकों को वैकल्पिक बाजार की ओर रुख करना चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार को चेतावनी दी है कि चूंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, इसलिए इस दक्षिण एशियाई देश पर अगले 24 घंटों में भारी नया टैरिफ आयाद किया जाएगा। ट्रंप ने पिछले हफ्ते ही भारत से आयातित उत्पादों पर 25 प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा की थी व रूस से तेल एवं गैस खरीदने की वजह से भारत पर अलग से जुमाना लगाने की बात भी कही थी। भारत ने आंकड़ों के जरिये अमेरिका और यूरोप को आईना दिखाया है कि अमेरिका खुद रूस के साथ व्यापार कर रहा है व भारत-रूस व्यापार पर उंगली उठा रहा है। पिछले साल कड़े प्रतिबंधों और टैरिफ के बावजूद, अमेरिका ने रूस के साथ लगभग 3.5 अरब डॉलर का व्यापार किया था। अमेरिका अब भी रूस से अपने परमाणु उद्योग के लिए यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की इंस्ट्री के लिए पैलेटिडियम, उर्वरक और कच्चे रसायन आयात करता है। यूक्रेन ये युद्ध शुरू होने के बाद भारत ने रूस से इसलिए तेल का आयात शुरू किया था, ताकि वैश्विक आपूर्ति तंत्र बना रहे व कीमतों को नियंत्रित रखा जा सके। तब खुद अमेरिका ने भारत के इस कदम का स्वागत किया था। खुद अमेरिका व यूरोप यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, वे वास्तव में युद्ध का अंत चाहते हैं तो यूक्रेन को हथियारों की मदद बंद कर दें। यूरोपीय संघ ने वर्ष 2024 में रूस के साथ 67.5 अरब यूरो मूल्य का वस्तु व्यापार किया। यह भारत के रूस के साथ उस वर्ष अथवा उसके बाद के कुल व्यापार से कहीं अधिक है। 2024 में यूरोप द्वारा रूस से एलएनजी का आयात 1.65 करोड़ टन तक पहुंच गया, जो 2022 में बने 1.521 करोड़ टन के पिछले रिकॉर्ड को भी पार कर गया। अमेरिका व यूरोप के दोहरे रथों को देखते हुए अमेरिका का भारत को निशाना बनाना अनुचित और तर्कहीन है। किसी भी प्रमुख अर्थव्यवस्था की तरह, भारत भी अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाता है। ट्रंप को इस नई चेतावनी के बाद रूस ने भारत का समर्थन करते हुए जवाब दिया है कि 'किसी भी देश को रूस के साथ व्यापार बंद करने के लिए मजबूर करना अवैध है। संप्रभु देशों को अपने व्यापार और आर्थिक सहयोग के लिए साझेदारों को चुनने का अधिकार है। भारतीय सेना ने भी अमेरिका को वर्ष 1971 की याद दिलाते हुए उसका असली चेहरा दिखाया है कि कैसे अमेरिका व चीन ने भारत से युद्ध में पाकिस्तान की मदद की थी। अभी टैरिफ दर में, आईएमएफ से लोन दिलाने में व ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिका ने अपनी पाकपरस्ती दिखाई है। इसलिए भारत को अमेरिका के असली चेहरे को पहचानते हुए अपने राष्ट्रीय हित में कदम उठाना चाहिए और ट्रंप को जैसे को तैसा की तर्ज पर जवाब देना चाहिए। भारत व अमेरिका का संबंध ट्रेड के इर्द-गिर्द ही रहा है, इसमें दोस्ती जैसी कोई बात नहीं है।



श्रद्धांजलि
ऑकारेश्वर पांडे

अलग झारखंड का सपना उठाने वाले कई थे, पर उसे सच करने वाला सिर्फ एक नाम था दिशोम गुरु। लोग कहते हैं, “गुरुजी सिर्फ नेता नहीं थे, आंदोलन की आत्मा थे।” उनके समर्थकों के लिए वे एक विचार थे, एक प्रतिरोध की पहचान। भारतीय राजनीति में झारखंड आंदोलन दरअसल आदिवासी पहचान की वह कहानी है, जिसे दिशोम गुरु ने खून-पसीने से लिखा। “गुरुजी का भरोसा सिर्फ लिखित वादों पर था, शब्दों से नहीं।” उन्होंने कसम खाई “जल, जंगल, जमीन की लड़ाई लड़ी जाएगी।”

नेमरा (रामगढ़) की गलियों से उठी उनकी आवाज ने 1960-70 के दशक में आवाम को झकझोला। जब धनकटनी आंदोलन शुरू हुआ, तब आदिवासी महिलाएं खेतों से धान काटकर ले जाती थीं, पुरुष तौर-कमान लिए परहे पर खड़े रहते थे। पर सिस्टम भी था, सरेंडर, गिरफ्तारी, गिरफ्तारी वारंट तक जारी। उनकी शुरूआत छोटी थी, पर असर बड़ा। धान जब्ती आंदोलन से शिबू सुखियों में आए। साहूकारों के गोदामों से अनाज निकालना, तौर-कमान लिए आदिवासी परहेदारों का पहरा, यह केवल विरोध नहीं था, यह सिस्टम को सीधी चुनौती थी। एक दिन शिबू सोरेन पारसनाथ के जंगलों में छिप गए, वहीं से आंदोलन चला “बाहरी” लोगों को निकालो, “झारखंड को शोषण से मुक्त करो” सपनों के इस आंदोलन ने उन्हें “दिशोम गुरु” की पहचान दी। 1973 में उन्होंने ए.के. राय और बिनाद बिहारी महतो के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाई। उस समय उनके नारे गूंजते थे “हमारी जमीन हमारी है, कोई दीकु (बाहरी) नहीं छीन सकता।” इसके साथ ही झारखंड आंदोलन तेज होने लगा। उस समय जेएमएफ का बनना कोई आसान बात नहीं थी, राजनीतिक विरोध, विभाजन और मानसिक खींचतान के बीच उन्होंने पार्टी को जीवंत रखा। तब लालू यादव ने 1998 में कहा था, “झारखंड मेरी लाश पर ही बनेगा,।” लेकिन शिबू सोरेन ने सभी विरोधों को पार करते हुए, कांग्रेस, आरजेडी और बीजेपी से गठबंधन बनाया और बातचीत से राज्य का मामला संसद तक पहुंचाया। शिबू सोरेन ने समझ लिया था कि झारखंड का सपना सिर्फ जंगलों में धरना देकर पूरा नहीं होगा, इसके

दिशोम गुरु से गुरुजी का कठिन सफर

दिशोम गुरु शिबू सोरेन चले गए। 10 बार सांसद, 3 बार मुख्यमंत्री, और उससे भी बढ़कर, वो शख्स जिसने तौर-कमान से नहीं, बल्कि संघर्ष और अपनी सियासी चालों से बिहार के आदिवासियों को उनका हक दिलाया। अलग झारखंड का सपना उठाने वाले कई थे, पर उसे सच करने वाला सिर्फ एक नाम था दिशोम गुरु। लोग कहते हैं, “गुरुजी सिर्फ नेता नहीं थे, आंदोलन की आत्मा थे।” उनके समर्थकों के लिए वे एक विचार थे, एक प्रतिरोध की पहचान। भारतीय राजनीति में झारखंड आंदोलन दरअसल आदिवासी पहचान की वह कहानी है, जिसे दिशोम गुरु ने खून-पसीने से लिखा। 11 जनवरी 1944 को रामगढ़ के नेमरा गांव में जन्मे शिबू सोरेन ने बचपन में साहूकारों की लूट देखी, खनन कंपनियों का लालच देखा। 1969 का अकाल, जब सरकारी गोदामों में अनाज सड़ रहा था और आदिवासी भूख से मर रहे थे, ने उनके भीतर ज्वाला भर दी। उन्होंने कसम खाई “जल, जंगल, जमीन को लड़ाई लड़ी जाएगी।”

नेमरा (रामगढ़) की गलियों से उठी उनकी आवाज ने 1960-70 के दशक में आवाम को झकझोला। जब धनकटनी आंदोलन शुरू हुआ, तब आदिवासी महिलाएं खेतों से धान काटकर ले जाती थीं, पुरुष तौर-कमान लिए परहे पर खड़े रहते थे। पर सिस्टम भी था, सरेंडर, गिरफ्तारी, गिरफ्तारी वारंट तक जारी। उनकी शुरूआत छोटी थी, पर असर बड़ा। धान जब्ती आंदोलन से शिबू सुखियों में आए। साहूकारों के गोदामों से अनाज निकालना, तौर-कमान लिए आदिवासी परहेदारों का पहरा, यह केवल विरोध नहीं था, यह सिस्टम को सीधी चुनौती थी। एक दिन शिबू सोरेन पारसनाथ के जंगलों में छिप गए, वहीं से आंदोलन चला “बाहरी” लोगों को निकालो, “झारखंड को शोषण से मुक्त करो” सपनों के इस आंदोलन ने उन्हें “दिशोम गुरु” की पहचान दी। 1973 में उन्होंने ए.के. राय और बिनाद बिहारी महतो के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाई। उस समय उनके नारे गूंजते थे “हमारी जमीन हमारी है, कोई दीकु (बाहरी) नहीं छीन सकता।” इसके साथ ही झारखंड आंदोलन तेज होने लगा। उस समय जेएमएफ का बनना कोई आसान बात नहीं थी, राजनीतिक विरोध, विभाजन और मानसिक खींचतान के बीच उन्होंने पार्टी को जीवंत रखा। तब लालू यादव ने 1998 में कहा था, “झारखंड मेरी लाश पर ही बनेगा,।” लेकिन शिबू सोरेन ने सभी विरोधों को पार करते हुए, कांग्रेस, आरजेडी और बीजेपी से गठबंधन बनाया और बातचीत से राज्य का मामला संसद तक पहुंचाया। शिबू सोरेन ने समझ लिया था कि झारखंड का सपना सिर्फ जंगलों में धरना देकर पूरा नहीं होगा, इसके

लिए दिल्ली की सत्ता के दरवाजे खोलने होंगे। और यही उन्होंने किया। 1989 में वी.पी. सिंह की सरकार को समर्थन, 1993 में नरसिम्हा राव को अविश्वास मत से बचाना, फिर 1999 में वाजपेयी की एनडीए सरकार से डील, शिबू हर बार सही मोड़ पर सही दांव खेलते रहे। कहते हैं, “गुरुजी का भरोसा सिर्फ लिखित वादों पर था, शब्दों पर नहीं।” और हुआ भी वही। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड बना। जयपाल सिंह मुंडा ने आंदोलन की शुरुआत की थी, लेकिन उसे मंजिल तक पहुंचाने वाला नाम था शिबू सोरेन। शिबू सोरेन की राजनीति का मूल था आदिवासी पहचान और जल-



जंगल-जमीन की रक्षा। उन्होंने सहूल जैसे त्योहारों को विरोध का मंच बनाया। खदान मजदूरों को संगठित किया और खनन कंपनियों की नाक में दम किया। उनकी पहल पर पेसा कानून आया, जिसने ग्राम सभाओं को जमीन पर फैसला लेने का अधिकार दिया। 2006 का वन अधिकार कानून भी उनकी जिद का नतीजा था। झारखंड से अरबों का कोयला और लौह अयस्क दिल्ली तक गया, पर गांवों तक सिर्फ गरीबी पहुंची। यही विडंबना है राज्य तो बना, पहचान मिली, पर आर्थिक न्याय अब भी अधूरा है। झारखंड देश के सबसे समृद्ध खनिज राज्यों में है। कोयले, लौह अयस्क और अन्य खनिजों से केंद्र को सालाना 40-45 हजार करोड़ से ज्यादा का हिस्सा मिलता है, जबकि राज्य को खुद के टैक्स से करीब 34 हजार करोड़ की आमदनी होती है। आसान शब्दों में खनिज निकलता है झारखंड से, फायदा जाता है दिल्ली को। यही सबसे बड़ी लड़ाई रही है। और यह लड़ाई आज भी जारी है। दिशोम गुरु का सफर सियासत और मुकदमों की सफेद-स्याह परछाइयों और विवादों से भरा रहा। 1975 में ‘बाहरी-विरोधी अभियान’, जिसमें 11 मौतें हुईं, उन पर हत्या का आरोप लगा। 1993 के अविश्वास मत में

रिश्वत का आरोप, 1994 में उनके निजी सचिव शशिनाथ झा की हत्या का मामला 2006 में सजा हुई, फिर 2007 में बरी हुए। फिर भी जनता ने उनका साथ नहीं छोड़ा। जेल से निकलकर भी चुनाव जीते। तीन बार मुख्यमंत्री बने। दस बार सांसद रहे। पार्टी के एक नेता कहते हैं “एक आदिवासी जब खड़ा होता है, तो उसे राजनीति में फंसाया भी जाता है। हेमंत सोरेन को भी जेल में डाला गया। पर क्या साबित हुआ? जनता अब इन चालों को अच्छी तरह समझने लगी है।” शिबू सोरेन के उपर मुकदमे, सजा और विवादों का बोझ था, पर जनता ने उनका साथ नहीं छोड़ा। उनके योगदान को लोग याद करते हैं, उन्होंने झारखंड का सपना रखा, आदिवासी पहचान को राष्ट्रीय विमर्श में रखा, और सबसे बड़ी बात कारपोरेट पावर को चुनौती दी। आज के दौर में विकास की जो रफ्तार है, वह आर्थिक अधिकारों के सवाल को और गहरा कर देती है, क्या राज्य की खनिज संपदा उसी जनता को लाभान्वित कर पाएगी जिसने इसे जन्म दिया? गुरुजी चले गए, पर सवाल वहीं हैं। शिबू सोरेन ने कभी बीजेपी का समर्थन किया, फिर आरजेडी से हाथ मिला, कभी कांग्रेस से तालमेल किया—हर कदम पर साबित किया कि राजनीतिक दृढ़ता और पहचान की चुनौतियाँ गठबंधन नीति से होकर गुजरती हैं।

“गुरुजी का भरोसा सिर्फ लिखित वादों पर था, शब्दों से नहीं।” भाषणों की नहीं, जमीन की राजनीति की गई। यह उन्हें अलग बनाता है। शिबू सोरेन ने झारखंड का सपना देखा, उसे संसद में गूंजाया, और आखिरकार राज्य के रूप में राजनीतिक हक की लड़ाई जीत ली। “इतिहास उन्हें सिर्फ नेता नहीं, बगावत और पहचान का प्रतीक लिखेगा...” लेकिन गरीबी, बेरोजगारी, और आर्थिक आत्मनिर्भरता का संघर्ष जारी है। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं। यह भरोसा सिर्फ बेटे पर नहीं, बल्कि उस इतिहास पर है जो शिबू सोरेन ने लिखा। हेमंत कहते हैं “विकास जरूरी है, पर वह हमारी पहचान को मिटाए नहीं।” आदिवासियों को राजनीतिक हक मिला, पर आर्थिक हक का सवाल अब भी अधूरा है। यही वह लड़ाई है जो आज हेमंत को लड़नी है। क्या हेमंत वह कर पाएंगे जो गुरुजी के दौर में अधूरा रह गया? जमीनी राजनीति की बिसात पर सतर्कता और सफलता से चल रहे हेमंत सोरेन के सामने उनका नारा “जल, जंगल, जमीन” अब भी गूंजता है। सवाल है कि क्या यह नारा सिर्फ झारखंड तक सीमित रहेगा या पिता की राह पर चलते हुए हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा को आदिवासी मुक्ति मोर्चा के रूप में स्थापित कर पाएंगे।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, वे उनके अपने विचार हैं। लेख पर अपनी प्रतिक्रिया edit@haribhoomi.com पर दें सकते हैं।)

प्लास्टिक संधि
राज कुमार सिन्हा



प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्ति के लिए विश्व की उम्मीदें

रिक्टरलैंड के जेनेवा में 5 से 14 अगस्त तक प्लास्टिक संधि के लिए अंतरराष्ट्रीय वार्ता समिति के प्रतिनिधिमंडल अंतिम बैठक के लिए एकत्रित हुए हैं। जहां प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय कानूनी रूप से बंधनकारी (आईएलबीआई) समझौता पर अंतिम दौर की बातचीत होगी। इसके पहले मई 2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा ने समुद्री पर्यावरण सहित प्लास्टिक प्रदूषण पर एक अंतरराष्ट्रीय, कानूनी रूप से बाध्यकारी उपाय विकसित करने के लिए प्रस्ताव पारित किया था। तब से अब तक पांच दौर की बातचीत पूर्ण हो चुकी है। अंतिम दौर की बातचीत अगस्त में होने जा रही है, जिसमें मुख्यतः प्लास्टिक उत्पादों के पूरे जीवन काल में प्राथमिक पॉलिमर उत्पादन से लेकर निपटान तक को ध्यान में रखें जाने की बात होगी। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार, प्लास्टिक की मांग सन् 2000 के बाद से लगभग दोगुनी हो गई है। एक हालिया अध्ययन के अनुसार, 2022 में फीडस्टॉक सहित 436.66 मिलियन टन पॉलिमर और प्लास्टिक का व्यापार हुआ, जिसमें अंतिम प्लास्टिक उत्पादों की मात्रा 111 मिलियन टन थी। आज, 99 फीसदी प्लास्टिक जीवाश्म ईंधन से बनता है। जीवाश्म ईंधनों को परिष्कृत करके मोनोमर्स (निर्माण खंड) और फिर पॉलिमर में संसाधित किया जाता है और उत्पादन के विभिन्न चरणों में मध्यवर्ती पदार्थ और रसायन (अध्ययनों से पता चलता है कि 16,000 से अधिक रसायनों का उपयोग किया जाता है) मिलाए जाते हैं। प्लास्टिक को विनियमित करने का अर्थ अनिवार्य रूप से इन पेटेंटआधारों को विनियमित करना होगा। प्लास्टिक उत्पादन और उपभोग को विनियमित करने के लिए, इन निर्माण खंडों, जिनमें इनका व्यापार भी शामिल है, पर ध्यान केंद्रित करना अनिवार्य है। विश्व भर के 600 से अधिक नागरिक समाज समूहों ने प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए एक मजबूत संधि की मांग करते हुए एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें प्लास्टिक उत्पादन में महत्वपूर्ण कटौती पर जोर दिया गया है। घोषणापत्र में कहा गया है कि जलवायु, जैव विविधता, मानव स्वास्थ्य, मानवाधिकारों और ग्रह की जीवन को सहारा देने और बनाए रखने की क्षमता पर हानिकारक प्रभाव डालता है। नागरिक समूहों ने वैश्विक प्लास्टिक उत्पादन में उल्लेखनीय कमी सुनिश्चित करने के लिए संधि की मांग की है। प्लास्टिक के जीवनचक्र में हानिकारक रसायनों के उन्मूलन, प्लास्टिक संबंधी जानकारी में पारदर्शिता, कार्यान्वयन के लिए स्पष्ट और पर्याप्त वित्तीय प्रतिबद्धताएं और तंत्र, प्रभावित समुदायों के लिए न्यायोचित परिवर्तन, झूठे समाधानों द्वारा जारी अपशिष्ट उपनिवेशवाद और पर्यावरणीय नस्लवाद का अंत, पुनः उपयोग और पुनः भरने की प्रणालियों को प्राथमिकता देने और मानव अधिकारों के संरक्षण का भी आह्वान किया है। कहा गया है कि प्लास्टिक और खतरनाक अपशिष्ट के उत्पादन में प्रयुक्त खतरनाक रसायनों पर बासेल, रॉटरडैम और स्टॉकहोम द्वारा नियंत्रण किया जाता है। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) द्वारा शासित होता है, और प्रस्तावित आईएलबीआई के प्रावधान डब्ल्यूटीओ समझौतों के विपरीत होंगे। इससे विकासशील देश और वे देश जो पॉलिमर व्यापार पर निर्भर हैं, व्यापार पर अंकुश लगाने से प्रभावित होंगे। हथ पर पर्यावरण पर 20वें अफ्रीकी मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (एमएससीएम-20) ने वैश्विक प्लास्टिक संधि का समर्थन करने की प्रतिबद्धता जताई है, तथा प्लास्टिक प्रदूषण पर अंतरराष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी साधन विकसित करने के लिए अंतर-सरकारी वार्ता समिति के साथ महाद्वीप की सहभागिता की आवश्यकता की पुष्टि की है। 18 जुलाई को नैरोबी में संपन्न हुई इस बैठक में स्वीकार किया गया कि अफ्रीका अपनी प्राकृतिक पूंजी की रक्षा के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है, जिसमें विविध पारिस्थितिकी तंत्र, पर्यटन, वायु, समृद्ध जैव विविधता से लेकर विशाल खनिज संपदा, मोटे पानी और समुद्री संसाधन शामिल हैं। इस कार्यक्रम में सदस्य देशों से पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए ‘संपूर्ण सरकार’ और ‘संपूर्ण समाज’ के दृष्टिकोण को अपनाने तथा समुदायों, महिलाओं और युवाओं को शामिल करने और उन्हें सशक्त बनाने का आह्वान किया गया, ताकि पर्यावरणीय संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके। भारत के नागरिक स्वयं प्रतिनिधिमंडल से आग्रह करते हैं कि इस होने वाले वार्ता में मानव स्वास्थ्य और अपस्ट्रीम समाधानों पर केंद्रित एक मजबूत वैश्विक प्लास्टिक संधि का समर्थन करें। जबकि प्लास्टिक पैकेजिंग, डिजाइन और सामग्री के उपयोग पर जीवनचक्र आकलन के आधार पर स्पष्ट लागू करने योग्य दिशानिर्देशों की तत्काल आवश्यकता है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, वे उनके अपने विचार हैं।)

मुंह के मौन से ज्यादा जरूरी ‘मन का मौन’



संकलित
दर्शन

हम सभी मनुष्य जन्मते ही अपना मुख चलाना शुरू कर देते हैं, जिसका प्रमाण है जन्म लेते ही शिशु का रोना। बोलना हमारी स्वाभाविक क्रिया है, जो हमें करनी ही पड़ती है। यह बात और है कि कभी-कभी बाहर के शोर में हम इतने खो जाते हैं कि ईश्वर का स्वर हमें सुनाई ही नहीं पड़ता। इसीलिए ही महापुरुषों से हमें एक उत्तम राय मिलती है कि सप्ताह में या माह में एक दिन अवश्य मौन रहे, परंतु हम मुख को तो बंद कर लेते हैं, परंतु हमारे मन का बोलना बंद नहीं हो पाता। इसलिए ही तो अधिकतर डाक्टर सभी मरीजों को कहते हैं कि ‘अपने मन को ज्यादा नहीं चलाओ।’ अर्थात् ‘मन का मौन’ करो। कहते हैं कि बिना हड्डी की जीभ जब बोलने लगती है, तो कड़्यों की हड्डियां तोड़ देती हैं। इसीलिए तो हमें यह बचपन से सिखाया जाता है कि पहले सोचो फिर बोलो, क्योंकि जैसे कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह मुख से निकला हुआ वचन भी वापस नहीं लिया जा सकता। इसका सबसे श्रेष्ठ उदहारण है महाभारत की कथा, जिससे हमें यह सीख मिलती है कि कैसे एक जुवान के फिसलने से संकटकाल का निर्माण हो गया। इसीलिए ‘कम बोलें-धीरे बोलें-मीठा बोलें।’ हम जब भी कुछ बोलें तो हमारे वचन दूसरों के लिए सुखदायी हों, न कि कांट चुभाने वाले दुःखदायी। संसार में ऐसे अनेक लोग हैं जिन्होंने कटू वचन बोलने के संस्कार के कारण अपन संबंधों में खटास पैदा कर ली है। इसलिए हमें सदैव सही समय और सही जगह पर सही शब्द का प्रयोग करना चाहिए।

अंतर्मन

ट्रंप की भारत को फिर धमकी, अगले 24 घण्टे में टैरिफ बढ़ाऊंगा

आज की पाती

कश्मीर से खतम होगा आतंकवाद

आतंकवाद एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। तथ्य को नकारना रेत में सिर छिपाना ही होगा। जिस तरह सरकार ने 2026 तक माओवादियों को अल्टीमेटम दे दिया है, उसके भय से आत्म समर्पण की गति तेज हो गई है। सीमापार संघर्ष की ताकत जानते हैं। सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के कारण घाटी में आतंकवादियों का आना कम हो गया है। कश्मीर में अमन है। जिस व्यक्ति के दिमाग पर कोई शक्ति हावी हो जाती है। सामान्य तर्क उसके सामने बेनामी होते हैं। पहले कश्मीर घाटी के युवाओं को पत्थरबाजी का जुनून सवार था। अब युवा कम्प्यूटर और इंटरनेट से जुड़ाव होने से मुख्यधारा में जुड़ चुके हैं। जुनून एक जीवन की पथरीली राहो पर ले जाता है और योग्यता वाला जुनून आदमी बनाने में अहम भूमिका बनाता है। पाकिस्तान की भूमिका डरावनी ही रही है। - *कविताल मांडोत, सूरत*

करंट अफेयर

जापान में परमाणु बम पीड़ित फैला रहे लोगों में जागरूकता

हिरोशिमा और नागासाकी पर 80 साल पहले हुए परमाणु बम हमले में जीवित बचे लोगों ने बढते परमाणु खतरों और वैश्विक नेताओं द्वारा परमाणु हथियारों को स्वीकार किए जाने पर चिंता जताई है। अमेरिका ने छह अगस्त, 1945 को हिरोशिमा पर और उसके तीन दिन बाद नागासाकी पर परमाणु बम से हमला किया था, जिससे उस वर्ष के अंत तक 2,00,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इस घातक हमले में कुछ लोग जीवित बच गए, लेकिन वे विकिरण संबंधी बीमारियों से ग्रस्त हो गए। परमाणु बम हमले के लगभग एक लाख लोग अभी जीवित हैं। उनमें से कई लोगों ने खुद को और अपने परिवारों को आज तक जारी भेदभाव से बचाने के लिए अपने अनुभवों को छिपा रखा है जबकि कुछ लोग खुद के साथ हुई भयावह विभीषिका के चलते अपनी आपबीती नहीं बता पाए। कुछ जीवित बचे लोगों ने अपने जीवन काल के अंतिम दिनों में परमाणु बम हमले के खिलाफ इस उमदी के साथ बोलना शुरू किया है, कि उनकी आपबीती सुन कर आसपाद दूसरे लोग परमाणु हथियारों के खान्दे के लिए दबाव बना सकें। परमाणु बम हमले के पीड़ित 83 वर्षीय कुनिहिको आईडा अनेक स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद अपनी सेवानिवृत्ति के वर्षों में लोगों को अपनी पीड़ा बता रहे हैं।



ऑफ बीट

कुछ कपड़े धोने पर सिकुड़ जाते हैं ? कैसे रोका जाए

कपड़े आखिर क्यों सिकुड़ते हैं, यह जानने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि कपड़े बनते कैसे हैं। सूती और लिनन जैसे सामान्य रेशे पीथों से हासिल होते हैं। ये रेशे अपने प्राकृतिक स्वरूप में अनियमित आकार के और झुर्रीदार होते हैं। अगर आप इन रेशों के अंदर गहराई से देखेंगे, तो आपको लाखों छोटे, लंबी-शृंखला वाले सेल्यूलोज अणु नजर आएंगे, जो प्राकृतिक रूप से सर्पिल आकार में मौजूद होते हैं। कपड़ा बनाने समय इन रेशों को यांत्रिक रूप से खींचा और मोड़ा जाता है, ताकि ये सेल्यूलोज शृंखलाएं सीधी हो जाएं और कतार में आ जाएं। इस प्रक्रिया में धिकने, लंबे धागे बनते हैं। रासायनिक स्तर पर, ये शृंखलाएं ‘हाइड्रोजन बॉन्ड’ से जुड़ी होती हैं, जो रेशों और धागों को मजबूत एवं लचीला बनाते हैं। ‘फाइबर मेमोरी’ के कारण ही कुछ कपड़ों पर आसानी से सिलवटें पड़ जाती हैं, जबकि कुछ कपड़े धोने के बाद सिकुड़ भी जाते हैं। कपड़े धोने के दौरान, गर्म पानी रेशों के ऊर्जा स्तर को बढ़ाने में मदद करता है—यानी वे ज़ीं से हिलते हैं, जिससे उन्हें एक-दूसरे से जोड़े रखने वाले ‘हाइड्रोजन बॉन्ड’ टूट जाते हैं। रेशों को जिस तरह से बुना या पिरोया जाता है, इसकी भी अहम भूमिका होती है। ढीले बुने हुए कपड़ों में धागों के बीच ज्यादा खुली जगह और लूप होते हैं, जो उन्हें न सिर्फ अधिक लचीला और सांस लेने योग्य बनाते हैं।



बिना बुलाए किसी के घर न जाएं

माता सती के पिता प्रजापति दक्ष शिव जी को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि शिव जी ने ब्रह्मा जी का पांच में से एक सिर काट दिया था। अपने पिता ब्रह्मा जी के साथ हुई इस घटना की वजह से दक्ष शिव जी को अपमानित करने के अलग-अलग अवसर खोजते रहते थे। दक्ष की पुत्री सती ने भगवान शिव से विवाह कर लिया था और दक्ष इस विवाह को रोक नहीं सके। विवाह के कुछ समय बाद दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया और इस यज्ञ में सभी देवी-देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। माता सती को नाराद से मालूम हुआ कि उनके पिता दक्ष यज्ञ करवा रहे हैं। सती इस यज्ञ में जाने के लिए तैयार हो गईं। शिव जी ने देवी सती को समझाया कि बिना बुलाए हमें यज्ञ जैसे आयोजन में नहीं जाना चाहिए, लेकिन शिव जी के समझाने पर भी देवी नहीं मानें और यज्ञ में चली गईं। जब सती यज्ञ स्थल पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि यज्ञ में शिव जी के अतिरिक्त सभी देवी-देवता आए हुए हैं। सती ने पिता दक्ष से शिव जी को न बुलाने का कारण पूछा तो दक्ष ने शिव जी के लिए अपमानजनक बातें कहना शुरू कर दीं। शिव जी का अपमान सती सहन नहीं कर सकीं और उन्होंने हवन कुंड में कूदकर अपनी हद त्याग दी। जब ये बात शिव जी को मालूम हुई तो वे बहुत क्रोधित हो गए। शिव जी के क्रोध से वीरभद्र प्रकट हुए। इसके बाद शिव जी के कहने पर वीरभद्र ने यज्ञ स्थल को उजाड़ दिया और दक्ष का सिर काट दिया।

ट्रेड

बचाव कार्य

उत्तरकाशी में पौखरे पलाड की घटना को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बात कर घटना की जानकारी ली। आईटीआरएस की 3 और एनडीआरएफ की 4 टीमा को घटनास्थल के लिए भेज दिया गया है, जो शीघ्र पहुंच कर बचाव कार्य में लगेगी। -*अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री*

गठबंधन में नहीं बसपा

बहुजन समाज पार्टी ना तो एनडीए गठबंधन के साथ है और ना ही कांग्रेस के इंडिया समूह (गठबंधन) के साथ है, ना ही अन्य किसी के साथ है, बल्कि अपनी ‘सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय’ के अनेकदरवासी सिद्धान्त व नीति पर चलने वाली पार्टी है। -*मायावती, पूर्व सीएम, उप्र*

धर्म विशेष के लोग

जो भी गैर-कानूनी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो क्योंकि अंधे थे अंधे होता फिर क्यों किसी जाति या धर्म विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। हम इसके खिलाफ कर्त जाएंगे। -*अखिलेश यादव, सांसद, सपा*

मलिक का निधन दुःख

पूर्व राज्यपाल व किसान हितैषी नेता सत्यपाल मलिक के निधन का समाचार बेहद दुःख है। वे बेबाकी और निडरता से सत्ता को सचवाईं का आँजना दिखाते रहे। शोककृत परिवारजनों और समर्थकों के प्रति नती गहरी संवेदना। -*मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस अध्यक्ष*

हमारा पता
हरिभूमि कार्यालय
नजीक इंडस पब्लिक स्कूल, दिल्ली रोड, रोहतक-124001 फोन: 9253681019-20 ई-मेल: haribhoomi@gmail.com वेब-साइट: www.haribhoomi.com

वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए टीम का चयन: भारतीय टीम के 10 में 9 पहलवान हरियाणा के

हरिभूमि न्यूज ▶ बहादुरगढ़

क्रोएशिया में अगले महीने होने जा रही सीनियर वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम का चयन हो गया है। टीम के चयन के लिए लखनऊ में हुए ट्रायल में हरियाणा की मिट्टी की ताकत ने अपनी धाक जमा दी। चयनित 10 पहलवानों में से 9 हरियाणा से हैं और इनमें से चार पहलवान झज्जर जिले से ताल्लुक रखते हैं। हरियाणा कुश्ती संघ के महासचिव डॉ. राकेश सांगवान ने दावा किया कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमारे ये पहलवान कई मेडल जीतकर देश का परचम लहराएंगे। दरअसल, आगामी 13 से 20 सितंबर तक क्रोएशिया में कुश्ती की सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन होगा। दुनियाभर के पहलवान चैंपियनशिप की तैयारी में जुटे हैं। इसी कड़ी में भारतीय प्री स्ट्राइल टीम चुनने के लिए लखनऊ में 4 अगस्त को ट्रायल्स हुए थे। जिनमें हरियाणा के पहलवानों का दमखम देखने को मिला।

झज्जर के अमन सहरावत, दीपक पूनिया, रजत रुहल और उदित दिखाएंगे दम

- लखनऊ में हुए ट्रायल में हरियाणा की मिट्टी की ताकत ने अपनी धाक जमा दी
- वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमारे ये पहलवान कई मेडल जीतकर देश का परचम लहराएंगे
- 13 से 20 सितंबर तक क्रोएशिया में कुश्ती की सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन होगा



बहादुरगढ़। वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चुनी गई टीम के साथ संघ के पदाधिकारी।

फोटो: हरिभूमि

टीम में ये खिलाड़ी शामिल

चयनित टीम में 57 केजी में अमन, 61 केजी में उदित, 65 केजी में सुजीत, 70 केजी में रोहित, 74 केजी में जयदीप, 79 केजी में अमित, 86 केजी में मुकुल देहिया, 92 केजी में दीपक पूनिया, 97 केजी में विक्रम और 125 केजी में रजत रुहल शामिल हैं। इन दस हरियाणवी पहलवानों में चार झज्जर जिले के गांवों से हैं। अमन जिले के गांव बिरोहड से है और ओलंपिक में देश के लिए मेडल जीत चुका है। जबकि सुरहा गांव का उदित भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा का लोहा मन्वा रहा है। अर्जुन अवंडी दीपक पूनिया गांव छारा से हैं। वहीं रोहड गांव का रजत रुहल हेवीवेट वर्ग में भारत की नई ताकत बनकर उभरा है। कोच वीरेंद्र आर्य, धर्मदेव दलाल आदि का कहना है कि हमारे पहलवान बेहद होनहार हैं। पूरे देश को इनसे मेडल की उम्मीदें रहती हैं।

खबर संक्षेप

राष्ट्रीय सब जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप कल से ग्रेटर नोएडा में
नई दिल्ली। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ ने मंगलवार को कहा कि ग्रेटर नोएडा में सात से 13 अगस्त तक होने वाली सब-जूनियर (अंडर-15) राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 400 लड़के और



300 लड़कियों सहित 700 से अधिक मुक्केबाज भाग लेंगे। इस प्रतियोगिता का आयोजन 15 भार वर्ग में किया जाएगा। हरियाणा लड़कियों के वर्ग में जबकि चंडीगढ़ लड़कों के वर्ग में गत विजेता है। तकनीकी नियमों के तहत होगी स्पर्धा राष्ट्रीय सब जूनियर चैंपियनशिप से पहले इस साल के शुरू में पुरुष, महिला और जूनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। मुक्केबाज विश्व मुक्केबाजी के तकनीकी नियमों के तहत प्रतियोगिता करेंगे, जिसमें 1.5 मिनट के तीन राउंड होंगे तथा राउंड के बीच में एक मिनट का विश्राम होगा। प्रतियोगिता में 10 अंकों की स्कोरिंग प्रणाली अपनाई जाएगी।

मप्र, हरियाणा, झारखंड व ओडिशा जूनियर महिला चैंपियनशिप में जीते

काकीनाडा। हॉकी मध्यप्रदेश, हॉकी हरियाणा, हॉकी झारखंड और ओडिशा हॉकी संघ ने यहां जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में मंगलवार को अपने अपने पूल मैच जीते। पहले डिजिजन ए मैच में हॉकी मध्यप्रदेश ने हॉकी चंडीगढ़ को 5-0 से हराया। कृष्णा शर्मा ने दो जबकि काजल, आयुषी पटेल और अन्नु ने एक-एक गोल किया। अगले मैच में हॉकी हरियाणा ने हॉकी बंगाल को 7-1 से मात दी। हॉकी झारखंड ने हॉकी कर्नाटक को 2-0 से मात दी। ओडिशा हॉकी संघ ने हॉकी आंध्र प्रदेश को 3-1 से हराया। डिजिजन बी में उत्तराखंड ने पुडुच्चेरी को 11-0 से मात दी जबकि तमिलनाडु और दिल्ली ने 3-3 से ड्रां खेला।

भारतीय सेना एफटी ने त्रिभुवन सेना एफसी को हराया

जमशेदपुर। पी क्रिकेटोफर कामेड के पहले हाफ में किये एकमात्र गोल की मदद से भारतीय सेना एफटी ने दस खिलाड़ियों तक खिलाड़ी त्रिभुवन सेना एफसी को ड्रं कप फुटबॉल ग्रुप सी के मैच में 1-0 से हरा दिया। नेपाल की त्रिभुवन सेना एफसी के तीन मैचों में एक ही अंक रहा जबकि भारतीय सेना के दो मैचों में तीन अंक हैं। भारतीय सेना के लिये क्रिकेटोफर ने 21वें मिनट में गोल दागा।

सब-जूनियर राष्ट्रीय तैराकी में कर्नाटक चैंपियन

बेंगलुरु। कर्नाटक 41वें सब जूनियर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में मंगलवार को यहां 104 अंक के साथ चैंपियन बना। मणिपुर 81 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रहा। राज्य के तैराक कोइजाम अथोइबा सिंह को 28 अंक के साथ सर्वश्रेष्ठ पुरुष तैराक चुना गया। गोव की पूर्वी रितेश नाईक 19 अंक के साथ सर्वश्रेष्ठ महिला तैराक रही। अथोइबा ने प्रतियोगिता के अंतिम दिन 100 मीटर फ्रीस्टाइल में 58.59 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता जबकि लड़कियों की 100 मीटर फ्रीस्टाइल में पूर्वी ने एक मिनट 4.40 सेकंड के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया।

नेशनल बैंक ओपन टेनिस टूर्नामेंट

शीर्ष वरीयता खिलाड़ी ज्वेरेव गत विजेता पोपिरिन को हराकर सेमीफाइनल में

एजेसी ▶▶ टोरंटो
शीर्ष वरीयता प्राप्त अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने पहला सेट गंवाने के बाद शानदार वापसी करके ऑस्ट्रेलिया के 18वें वरीयता प्राप्त एलेक्सी पोपिरिन को हराकर नेशनल बैंक ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। जर्मन खिलाड़ी और यहां 2017 के चैंपियन ज्वेरेव ने पिछली बार के विजेता पोपिरिन को 6-7 (8), 6-4, 6-3 से पराजित किया। सेमीफाइनल में उनका मुकाबला रूस के कारेन खचानोव या अमेरिका के एलेक्स मिशेलसन से होगा। दुनिया में तीसरे नंबर के खिलाड़ी ज्वेरेव 75वें बार एटीपी टूर के सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। वह अपने कुल 25वें और एटीपी 1000 मास्टर्स टूर्नामेंट में आठवें खिताब की तलाश में हैं।



कनाडा की मबोको सेमीफाइनल में, अब मुकाबला रयबाकिना से

मॉन्ट्रियल। कनाडा की किशोरी विकटोरिया मबोको ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए नेशनल बैंक ओपन टेनिस टूर्नामेंट में स्पेन की जेसिका बुजास मानेरो को 6-4, 6-2 से हराकर अपने करियर के पहले डब्ल्यूटीए टूर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। शीर्ष वरीयता प्राप्त कोको गॉफ को हराने के दो दिन बाद टोरंटो की रहने वाली 18 वर्षीय खिलाड़ी मबोको को लय हासिल करने में देर लगी लेकिन उन्होंने जल्द ही मैच पर नियंत्रण बना दिया और सीधे सेट में जीत दर्ज की।

6 साल बाद मबोको सेमीफाइनल में पहुंचीं

मबोको 2019 में बियांका एंड्रिस्कू के खिलाफ जीतने के बाद से इस डब्ल्यूटीए 1000 प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली कनाडा की पहली खिलाड़ी हैं। वह टोरंटो में 2015 में बेलिंडा बेनकिच के बाद सेमीफाइनल में पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी भी हैं।

मुकाबला अब कजाकिस्तानी से

मबोको का सामना अब एलेना रयबाकिना से होगा, जिन्होंने मार्त कोरन्युक के हथ में चोट लग जाने के कारण मैच के बीच में हट जाने के बाद सेमीफाइनल में जगह बनाई। यूक्रेन की खिलाड़ी ने जब मैच से हटने का फैसला किया तब कजाकिस्तान की नौवीं वरीयता प्राप्त रयबाकिना 6-1, 2-1 से आगे चल रही थीं।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट

एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वालों में मुथैया नंबर वन पर



एजेसी ▶▶ नई दिल्ली

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा विकेट चटकाना किसी भी गेंदबाज के लिए उत्कृष्ट फॉर्म, फिटनेस और निरंतरता का प्रतीक होता है। जब एक गेंदबाज पूरे साल सभी प्रारूप में विपक्षी बल्लेबाजों के लिए चुनौती बन जाता है तब वह आंकड़ों में भी अपना दबदबा दर्ज करता है। ऐसे में आइए जानते हैं उन घातक गेंदबाजों के बारे में जिन्होंने एक साल में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट चटकाकर क्रिकेट इतिहास में अपनी अलग पहचान बनाई।

(128 विकेट, 2006)

दूसरे स्थान पर भी मुरलीधरन ही हैं। उन्होंने साल 2006 में 40 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले थे और 854.2 ओवर के साथ 147 मेडन ओवर थे। वह 128 विकेट लेने में सफल रहे थे।

शेन वॉन (120 विकेट, 1994)

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व महान गेंदबाज शेन वॉन इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने साल 1994 में 39 मुकाबले खेले थे और इस दौरान 902.2 ओवर गेंदबाजी की थी। वॉन ने 230 मेडन ओवर के साथ 120 विकेट चटकाए थे। उनकी इकॉनॉमी रेट 3.14 की रही थी। उन्होंने 9 बार 5 विकेट हॉल और 5 बार दोहरे पारियों को मिलाकर 10 विकेट लिए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 8/71 का रहा था।

वलेन मैक्वा (119 विकेट, 1999)

कंगारू टीम के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज वलेन मैक्वा इस सूची में चौथे स्थान पर हैं। उन्होंने साल 1999 में 41 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले थे और इस दौरान मैक्वा ने 802.2 ओवर गेंदबाजी की थी। 187 मेडन ओवर के साथ उन्होंने 20.23 की औसत से 119 विकेट लिए थे। इस खिलाड़ी ने 6 बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किए थे और 1 बार दोहरे पारियों को मिलाकर 10 विकेट लिखा था।

चेन्नई वैंडमास्टर्स

अर्जुन एरिगेसी को गुजराती और गिरि से मिलेगी कड़ी चुनौती

चेन्नई। भारत के नंबर एक खिलाड़ी अर्जुन एरिगेसी को सोमवार 11 अगस्त से शुरू हो रहे चेन्नई ग्रैंडमास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट के तीसरे सत्र में नीदरलैंड के अनीश गिरि और अपने हम्बतन विदित गुजराती से कड़ी चुनौती मिलेगी। इस टूर्नामेंट में विजेता को एक करोड़ रुपये मिलेंगे। पहली बार इसमें मास्टर्स और चैलेंजर्स वर्ग में क्लासिकल राउंड रॉबिन प्रारूप में नौ से अधिक दौर खेले जायेंगे। इससे पहले दो सत्र में सात दौर ही खेले जाते थे।

ये अन्य खिलाड़ी भी लेंगे भाग

इसमें 19 ग्रैंडमास्टर्स भाग लेंगे और फिडे सर्किट अंक भी मिलेंगे जो 2026 कैडिडेट्स टूर्नामेंट में जगह पाने के लिये अहम होंगे। टूर्नामेंट में निहाल सरिन और जर्मनी के विसेंट केमेर जैसे खिलाड़ी भी भाग ले रहे हैं। चैलेंजर्स वर्ग में डी हरिका, आर वैशाली, हर्षवर्धन जीबी, अभिमन्यु पुराणिक, ग्रैंडमास्टर्स अधिबान भास्करन भी हिस्सा लेंगे।

वेस्टइंडीज-पाक के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज 8 से, रिजवान संभालेंगे कप्तानी

एजेसी ▶▶ त्रिनिदाद

पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने हाल ही में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ सम्पन्न हुई टी-20 सीरीज को 2-1 से जीतने में सफलता हासिल की थी। टी-20 सीरीज में पाकिस्तान ने पहला और तीसरा मैच जीता, जबकि दूसरा मुकाबला मेजबान टीम ने जीता था। अब दोनों देशों के बीच वनडे सीरीज की शुरुआत 8 अगस्त से हो जाएगी। अभी वेस्टइंडीज की टीम का ऐलान नहीं हुआ है। इस सीरीज के लिए दोनों टीमों, शेड्यूल और अन्य अहम जानकारी पर एक नजर डालते हैं।



रिजवान करेंगे पाकिस्तान की कप्तानी

मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान की वनडे टीम की कप्तानी करेंगे। हसन नवाज वनडे टीम में एकमात्र अनकेड खिलाड़ी हैं। इनके अलावा बाबर आजम और शाहीन अफरोदी भी वनडे टीम में खेलते दिखेंगे। ये खिलाड़ी टी-20 सीरीज में नहीं खेलें थे।

ऐसा है वनडे सीरीज का शेड्यूल

पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच वनडे सीरीज की शुरुआत 8 अगस्त को होने वाले पहले मुकाबले से हो जाएगी। इसके बाद तीसरा मुकाबला 12 अगस्त को खेला जाएगा। ये तीनों वनडे मैच त्रिनिदाद के बायन लारा स्टेडियम में खेले जाएंगे। भारतीय समयानुसार पहला वनडे रात 11:30 बजे से और आखिरी 2 वनडे मैच शाम 7 बजे से खेले जाएंगे। अभी वेस्टइंडीज की टीम का ऐलान नहीं हुआ है। वेस्टइंडीज का पलड़ा रहा है भारी अब तक दोनों देशों की मिडिल में वेस्टइंडीज ने ज्यादा मैच जीते हैं। अब तक दोनों टीमों वनडे प्रारूप में कुल 137 मैच में आपस में भिड़ी थीं, जिसमें से वेस्टइंडीज ने 71 मैच जीते थे, जबकि पाकिस्तान ने 63 मुकाबले अपने नाम किए थे। इस बीच 3 मैच टाई भी रहे थे।

एएफसी अंडर-17 एशिया कप फुटबॉल क्वालीफायर

एशियाई कप 2026 के क्वालीफायर की मेजबानी करेगा अहमदाबाद

एजेसी ▶▶ नई दिल्ली

भारत 22 से 30 नवंबर तब होने वाले एएफसी अंडर-17 एशिया कप फुटबॉल क्वालीफायर की मेजबानी करने वाले सात मेजबानों में शामिल है। अहमदाबाद के 'द एरेना' में सभी मैचों का आयोजन किया जाएगा। क्वालीफायर के ड्रा सात अगस्त को होंगे। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कल्याण चौबे ने कहा, "एएफसी अंडर-17 एशियाई कप सऊदी अरब 2026 क्वालीफायर के मेजबान देशों में शामिल होना भारत के लिए बेहद गर्व की बात है और अहमदाबाद में आयोजन को लेकर मैं काफी खुश हूँ।



टीमों को 6 पाँट में किया गया है विभाजित

चौबे ने बताया कि 6 क्वालीफायर में भाग लेने वाली 38 टीम को वरीयता और पाँट आवंटन सिद्धांत के आधार पर छह पाँट में विभाजित किया गया है जो पिछले तीन टूर्नामेंट (2025, 2023 और 2018) में टीम के प्रदर्शन के आधार पर है। भारत पाँट दो में है। ड्रा के उद्देश्य से उसे एक अतिरिक्त मेजबान पाँट में रखा जाएगा जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी मेजबान अलग-अलग समूहों में हों। चीन, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, किर्गिस्तान और जोर्डन अन्य छह मेजबान हैं जिन्हें भारत के समूह में नहीं रखा जा सकता।

38 देशों की टीमों ले रहीं भाग

क्वालीफायर में हिस्सा ले रहे 38 देशों को सात ग्रुप (छह टीम के तीन ग्रुप, पांच टीम के चार ग्रुप) में बांटा गया है। प्रत्येक ग्रुप का विजेता एएफसी अंडर-17 एशियाई कप सऊदी अरब 2026 के लिए क्वालीफाई करेगा। फीफा अंडर-17 विश्व कप कतर 2025 में खेलने वाली नौ टीम पहले ही सऊदी अरब में होने वाले टूर्नामेंट में सीधे प्रवेश कर चुकी हैं।

2026 क्वालीफायर ड्रा के लिए पाँट

- पाँट 1: ऑस्ट्रेलिया, यमन, ईरान, ओमान, थाईलैंड।
 - पाँट 2: अफगानिस्तान, मलेशिया, इराक, बांग्लादेश, लाओस, कुवैत।
 - पाँट 3: सिंगापुर, बहरीन, फिलिपींस, तुर्कमेनिस्तान, फलस्तीन।
 - पाँट 4: सिरिया, मंगोलिया, कंबोडिया, हांगकांग, चीनी ताइपे, युनई वारुसल्लाम।
 - पाँट 5: नेपाल, उत्तरी मारियाना द्वीप, गुआम, मालदीव, तिमोर-लेस्ते, लेबनान।
 - पाँट 6: मकाऊ, श्रीलंका, पाकिस्तान।
- मेजबान पाँट: चीन, वियतनाम, थाईलैंड, भारत, म्यांमार, किर्गिस्तान और जोर्डन।

खबर संक्षेप

विदेशी पर्यटकों को यूएस में प्रवेश को पंद्रह हजार डॉलर का बांड देना होगा न्यूयॉर्क। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन एक प्रायोगिक कार्यक्रम लागू कर रहा है जिसके तहत पर्यटक या व्यावसायिक वीजा पर अमेरिका आने वाले विदेशी आगंतुकों को 15,000 अमेरिकी डॉलर तक का "बांड" भरना पड़ेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे अपनी वीजा अवधि खत्म होने के बाद भी देश में न रुके। इस कार्यक्रम के दायरे में आने वाले देशों की घोषणा अभी नहीं की गई है। अमेरिकी विदेश विभाग ने एक "अस्थायी अंतिम नियम" जारी किया है।

अचानक भारत पहुंची यूक्रेन की 'फर्स्ट लेडी' जयपुर। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेन्स्की की पत्नी और यूक्रेन की फर्स्ट लेडी ओलेना जेलेन्स्का स्पेशल फ्लाइट से जापान जा रही थीं। अचानक उनका विमान भारत के जयपुर एयरपोर्ट पर लैंड किया। दरअसल, ओलेना जेलेन्स्का का विमान फ्यूल भरवाने के लिए जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कुछ समय के लिए रुका था।

इमरान की जेल से रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन इस्लामाबाद/लाहौर। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी ने दो साल पहले भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार कर लिये गये पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई की मांग करते हुए मंगलवार को देश के विभिन्न हिस्सों में विरोध रैलियां निकालीं। पार्टी ने दावा किया कि सड़कों पर उतरे उसके 500 से अधिक कार्यकर्ताओं और समर्थकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

तख्तापलट के आरोप में पूर्व राष्ट्रपति नजरबंद साओ पाउलो। ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति जायर बोलसोनारो को नजरबंद करने का आदेश दिया। आरोप है कि उन्होंने 2022 का चुनाव हारने के बाद कथित तौर पर तख्तापलट करने की कोशिश का नेतृत्व किया था। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश डी मोरेस ने आदेश जारी करते हुए कहा कि बोलसोनारो ने अपने बेटे के सोशल मीडिया चैनलों पर सामग्री पोस्ट करके उन पर लगाए गए एहतियाती उपायों का उल्लंघन किया है।

शिबू सोरेन पंचतत्व में विलीन नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को एक दंपति की तलाक की अर्जा मंजूर कर ली और साथ ही व्यक्ति को निर्देश दिया कि वह अलग रह रही पत्नी को चार करोड़ रुपये का मुंबई स्थित फ्लैट सौंप दे। प्रधान न्यायाधीश बी आर गवाड़, न्यायमूर्ति के विनोद चंदा और न्यायमूर्ति एन जी अजयारिया की पीठ ने व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए (महिला के साथ क्रूरता करना), 406 (आपराधिक विश्वासघात) और धारा 34 के तहत शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को भी रद्द कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि पिछले आठ वर्षों से दोनों पक्षों के बीच कटु संबंध हैं और कई कानूनी कार्यवाहियां लंबित हैं, जिससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि उनकी शादीपूरी तरह से टूट चुकी है। पीठ ने कहा कि हम संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत दायर अर्जा को भी स्वीकार करते हैं।

आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में जताया समर्थन हरिभूमि ब्यूरो नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और फिलीपीन अपनी मर्जी से मित्र और नियति से साझेदार हैं। उन्होंने यह टिप्पणी ऐसे समय में की, जब दोनों देशों ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाते हुए अपने सशस्त्र बलों के बीच तालमेल बढ़ाने पर जोर दिया। मोदी और फिलीपीन के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर के बीच यहां संपन्न द्विपक्षीय वार्ता के बाद दोनों देशों ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा की। एक दिन पहले दोनों देशों की नौसेनाओं ने संयुक्त अभ्यास किया था। मोदी ने कहा कि भारत और फिलीपीन अपनी मर्जी से मित्र और नियति से साझेदार हैं। हिंद महासागर से लेकर प्रशांत महासागर तक, हम साझा मूल्यों के तहत एकजुट हैं। हमारी दोस्ती अतीत की साझेदारी नहीं है, भविष्य के लिए वादा है। दोनों देशों ने नौ समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें रणनीतिक साझेदारी की घोषणा एवं कार्यान्वयन, दोनों देशों की सेना, वायु सेना और नौसेना के बीच वार्ता के लिए संदर्भ की शर्त व बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण इस्तेमाल पर सहयोग शामिल है।

राजनीतिक यात्रा समाजवादी विचारधारा वाले एक छात्र नेता के रूप में शुरू हुई भाषा नई दिल्ली। अनुभवी नेता सत्यपाल मलिक का पांच दशक लंबा राजनीतिक करियर कई राजनीतिक दलों से गुजरा और वह इस दौरान कई उच्च-स्तरीय संवैधानिक पदों पर भी रहे जिसके बाद वह उसी सत्ता प्रतिष्ठान के मुखर आलोचक बन गए जिसकी उन्होंने सेवा की थी। उन्होंने चार राज्यों - बिहार (2017), जम्मू और कश्मीर (2018), गोवा (2019) और मेघालय (2020) के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। लेकिन उनका सबसे प्रभावशाली कार्यकाल अगस्त 2018 में शुरू हुआ, जब

राजनीतिक जीवन कई दलों में बदलता रहा उन्हें जम्मू और कश्मीर का राज्यपाल नियुक्त किया गया। इस कार्यकाल में दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटीं। पहला, 2019 का पुलवामा आतंकवादी हमला जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए तथा दूसरा, पांच अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बना दिया गया तथा तत्कालीन राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों--जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया। मलिक जम्मू-कश्मीर राज्य के अंतिम राज्यपाल थे। मलिक (79) कुछ

समय से यहां एक अस्पताल में भर्ती थे और मंगलवार को उनका निधन हो गया। वर्ष 2019 में आज के ही दिन अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाया गया था। यद्यपि वह भाजपा में एक वफादार के रूप में प्रमुखता से उभरे, लेकिन हाल के वर्षों में उनकी पहचान केंद्र सरकार की नीतियों के मुखर आलोचक के रूप में होने लगी थी, जिससे उनकी सार्वजनिक छवि एक अनुभवी प्रशासक से एक मुखर असंतुष्ट की बन गई थी। जम्मू-कश्मीर से उन्हें गोवा स्थानांतरित कर दिया गया था, जहां राज्य सरकार के साथ उनके रिश्ते खराब हो गए क्योंकि उन्होंने कोविड-19 से निपटने के उनके

प्रयासों की खुलेआम आलोचना की और उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। गोवा से उन्हें मेघालय भेज दिया गया जो बतौर राज्यपाल उनका अंतिम कार्यभार था। राज्यपाल पद से सेवानिवृत्त होने पर, उन्होंने महत्वपूर्ण मामलों पर सार्वजनिक रूप से केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने यह भी कहा था कि पुलवामा हमला सरकारी उदासीनता का परिणाम था। उन्होंने तीन केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध का मुखर समर्थन किया। उनका तर्क था कि केंद्र सरकार ने उनकी (किसानों की) बात नहीं सुनी। अपने जीवन के अंतिम दिनों में, मलिक का नाम

उप के बागपत में हुआ था जन्म मलिक का जन्म 24 जुलाई, 1946 को उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के हिस्सावद गांव में हुआ था। उनकी राजनीतिक यात्रा समाजवादी विचारधारा वाले एक छात्र नेता के रूप में शुरू हुई, लेकिन बाद में उनका राजनीतिक जीवन कई दलों में बदलता रहा। वह भारतीय क्रांति दल (बीकेडी) से कांग्रेस में चले गए, फिर जनता दल और अंततः भाजपा में शामिल हो गए। जाट नेता मलिक पहली बार 1974 में चरण सिंह की बीकेडी से उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए थे। मलिक दो बार राज्यसभा के लिए चुने गए - 1980

से 1986 तक और फिर 1986 से 1989 तक। फिर उन्होंने जनता दल के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया। वह अलीगढ़ संसदीय सीट से जीत हासिल कर लोकसभा पहुंचे। तत्कालीन वी पी सिंह सरकार ने उन्हें संसदीय कार्य और पर्यटन राज्य मंत्री नियुक्त किया। वी पी सिंह सरकार के गिर जाने और उसके बाद जनता दल में उथल-पुथल होने के बाद, मलिक भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा में वह पार्टी उपाध्यक्ष बने और किसान मोर्चा (किसान प्रकोष्ठ) के प्रमारी के रूप में भी कार्य किया।

इस साल मई में दाखिल किये गये सीबीआई के आरोपपत्रों में भी शामिल था, जो 2,200 करोड़ की कीरू जलविद्युत परियोजना में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में थे। उन्होंने अस्पताल से ही इन आरोपों का पुरजोर खंडन किया और इसे 'राजनीतिक प्रतिशोध' बताया था।

रद्राक्ष वितरण अचानक बंद होने पर भीड़ हुई बेकाबू प्रदीप मिश्रा के कुबेरेइवर धाम में भगदड़, दो महिलाओं की मौत

हरिभूमि ब्यूरो नई दिल्ली। सीहोर के कुबेरेइवर धाम में मंगलवार को रुद्राक्ष वितरण के दौरान भारी भीड़ के कारण मची भगदड़ में दो महिलाओं की मौत हो गई और 10 से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए। भीड़ इतनी बढ़ गई कि ठहरने और दर्शन की व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गईं। प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं।

जिले के प्रसिद्ध कुबेरेइवर धाम में मंगलवार को उस समय हृदयविदारक हादसा हो गया जब रुद्राक्ष वितरण अचानक बंद कर दिया गया। इस दौरान भीड़ बेकाबू हो गई और अफरा-तफरी में दो महिलाएं दब गईं, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। करीब 10 अन्य श्रद्धालु घायल हुए, जिनमें से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद तीन घायलों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने दो महिलाओं को मृत घोषित कर दिया। दोनों की उम्र लगभग 50 वर्ष बताई जा रही है। अभी तक मृत महिलाओं में एक महिला 56 वर्षीय जसवंती बहन (ओमनगर, राजकोट, गुजरात) की पहचान हुई है।

कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए

कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए

कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए

कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए

कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए

कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए

कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए

कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए

कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए

कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए

सत्यपाल मलिक : वफादार से विवादास्पद आलोचक राजनेता तक

राजनीतिक यात्रा समाजवादी विचारधारा वाले एक छात्र नेता के रूप में शुरू हुई

पहली बार 1974 में चरण सिंह की बीकेडी से उपर विस के लिए चुने गए थे



सत्यपाल मलिक

भाषा नई दिल्ली

अनुभवी नेता सत्यपाल मलिक का पांच दशक लंबा राजनीतिक करियर कई राजनीतिक दलों से गुजरा और वह इस दौरान कई उच्च-स्तरीय संवैधानिक पदों पर भी रहे जिसके बाद वह उसी सत्ता प्रतिष्ठान के मुखर आलोचक बन गए जिसकी उन्होंने सेवा की थी।

उन्होंने चार राज्यों - बिहार (2017), जम्मू और कश्मीर (2018), गोवा (2019) और मेघालय (2020) के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। लेकिन उनका सबसे प्रभावशाली कार्यकाल अगस्त 2018 में शुरू हुआ, जब

राजनीतिक जीवन कई दलों में बदलता रहा

उन्हें जम्मू और कश्मीर का राज्यपाल नियुक्त किया गया। इस कार्यकाल में दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटीं। पहला, 2019 का पुलवामा आतंकवादी हमला जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए तथा दूसरा, पांच अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बना दिया गया तथा तत्कालीन राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों--जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया। मलिक जम्मू-कश्मीर राज्य के अंतिम राज्यपाल थे। मलिक (79) कुछ

समय से यहां एक अस्पताल में भर्ती थे और मंगलवार को उनका निधन हो गया। वर्ष 2019 में आज के ही दिन अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाया गया था। यद्यपि वह भाजपा में एक वफादार के रूप में प्रमुखता से उभरे, लेकिन हाल के वर्षों में उनकी पहचान केंद्र सरकार की नीतियों के मुखर आलोचक के रूप में होने लगी थी, जिससे उनकी सार्वजनिक छवि एक अनुभवी प्रशासक से एक मुखर असंतुष्ट की बन गई थी। जम्मू-कश्मीर से उन्हें गोवा स्थानांतरित कर दिया गया था, जहां राज्य सरकार के साथ उनके रिश्ते खराब हो गए क्योंकि उन्होंने कोविड-19 से निपटने के उनके

प्रयासों की खुलेआम आलोचना की और उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। गोवा से उन्हें मेघालय भेज दिया गया जो बतौर राज्यपाल उनका अंतिम कार्यभार था। राज्यपाल पद से सेवानिवृत्त होने पर, उन्होंने महत्वपूर्ण मामलों पर सार्वजनिक रूप से केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने यह भी कहा था कि पुलवामा हमला सरकारी उदासीनता का परिणाम था। उन्होंने तीन केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध का मुखर समर्थन किया। उनका तर्क था कि केंद्र सरकार ने उनकी (किसानों की) बात नहीं सुनी। अपने जीवन के अंतिम दिनों में, मलिक का नाम

उप के बागपत में हुआ था जन्म मलिक का जन्म 24 जुलाई, 1946 को उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के हिस्सावद गांव में हुआ था। उनकी राजनीतिक यात्रा समाजवादी विचारधारा वाले एक छात्र नेता के रूप में शुरू हुई, लेकिन बाद में उनका राजनीतिक जीवन कई दलों में बदलता रहा। वह भारतीय क्रांति दल (बीकेडी) से कांग्रेस में चले गए, फिर जनता दल और अंततः भाजपा में शामिल हो गए। जाट नेता मलिक पहली बार 1974 में चरण सिंह की बीकेडी से उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए थे। मलिक दो बार राज्यसभा के लिए चुने गए - 1980

से 1986 तक और फिर 1986 से 1989 तक। फिर उन्होंने जनता दल के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया। वह अलीगढ़ संसदीय सीट से जीत हासिल कर लोकसभा पहुंचे। तत्कालीन वी पी सिंह सरकार ने उन्हें संसदीय कार्य और पर्यटन राज्य मंत्री नियुक्त किया। वी पी सिंह सरकार के गिर जाने और उसके बाद जनता दल में उथल-पुथल होने के बाद, मलिक भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा में वह पार्टी उपाध्यक्ष बने और किसान मोर्चा (किसान प्रकोष्ठ) के प्रमारी के रूप में भी कार्य किया।

इस साल मई में दाखिल किये गये सीबीआई के आरोपपत्रों में भी शामिल था, जो 2,200 करोड़ की कीरू जलविद्युत परियोजना में

कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में थे। उन्होंने अस्पताल से ही इन आरोपों का पुरजोर खंडन किया और इसे 'राजनीतिक प्रतिशोध' बताया था।

फिलीपीन के राष्ट्रपति फर्डिनेंड पांच दिवसीय यात्रा पर, प्रधानमंत्री से की वार्ता

भारत और फिलीपीन अपनी मर्जी से मित्र और नियति से साझेदार: मोदी

हरिभूमि ब्यूरो नई दिल्ली

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और फिलीपीन अपनी मर्जी से मित्र और नियति से साझेदार हैं। उन्होंने यह टिप्पणी ऐसे समय में की, जब दोनों देशों ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाते हुए अपने सशस्त्र बलों के बीच तालमेल बढ़ाने पर जोर दिया। मोदी और फिलीपीन के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर के बीच यहां संपन्न द्विपक्षीय वार्ता के बाद दोनों देशों ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा की। एक दिन पहले दोनों देशों की नौसेनाओं ने संयुक्त अभ्यास किया था। मोदी ने कहा कि भारत और फिलीपीन अपनी मर्जी से मित्र और नियति से साझेदार हैं। हिंद महासागर से लेकर प्रशांत महासागर तक, हम साझा मूल्यों के तहत एकजुट हैं। हमारी दोस्ती अतीत की साझेदारी नहीं है, भविष्य के लिए वादा है। दोनों देशों ने नौ समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें रणनीतिक साझेदारी की घोषणा एवं कार्यान्वयन, दोनों देशों की सेना, वायु सेना और नौसेना के बीच वार्ता के लिए संदर्भ की शर्त व बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण इस्तेमाल पर सहयोग शामिल है।

दोनों देशों ने सशस्त्र बलों के बीच तालमेल बढ़ाने पर जोर दिया



मोदी और दुतेरे

फिलीपीन में त्वरित प्रभाव परियोजनाओं की संख्या बढ़ाएगा भारत

दक्षिण चीन सागर में शांति में भारत की स्थायी रुचि

विदेश मंत्रालय ने कहा कि दक्षिण चीन सागर पर भारत का रुख स्पष्ट एवं सतत है तथा वह उसे वैश्विक साझा क्षेत्र मानता है। फिलीपीन के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर की वर्तमान भारत यात्रा को लेकर यहां आयोजित एक विशेष प्रेसवार्ता के दौरान पूछे गए सवाल के उत्तर में विदेश मंत्रालय के सचिव (पूर्व) पी. कुमारन ने कहा कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता में भारत की स्थायी रुचि है।

मोदी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा: मार्कोस

राष्ट्रपति मार्कोस ने कहा कि वह भारत के साथ एकजुटता का संदेश लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद की चुनौतियों के बावजूद, मैं भारत को विकसित भारत 2047 के सपने की ओर मजबूती से आगे बढ़ते देखने पर बधाई देता हूँ। यह सब पीएम मोदी के सक्षम नेतृत्व में हो रहा है।

मोदी और मार्कोस ने एक डाक टिकट जारी किया

मोदी ने कहा कि फिलीपीन भारत की 'एक्ट इस्ट नीति' और 'महासागर' (क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक एवं समग्र उन्नति) दृष्टिकोण में एक अहम साझेदार है। हम हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, समृद्धि और नियम-आधारित व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुसार नौवहन की स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। भारत और फिलीपीन दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। मोदी और मार्कोस ने एक डाक टिकट जारी किया।

मनीला। भारत और फिलीपीन ने विवादित दक्षिण चीन सागर में पहली बार संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है।

भारत-फिलीपींस का पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास



भारत-फिलीपींस का पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास

शिबू सोरेन पंचतत्व में विलीन



नेमरा (झारखंड) (भाषा)। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का मंगलवार को उनके पैतृक गांव नेमरा में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर हजारों लोगों ने 'दिशोम गुरु' को नम आखों से अंतिम विदाई दी जिनमें ग्रामीण, राजनीतिक हस्तियों और समाज के सभी वर्गों के लोग शामिल थे। शिबू सोरेन को लोग प्यार से 'दिशोम गुरु' (भूमि के नेता) कहते थे। उनका सोमवार को 81 वर्ष की आयु में दिल्ली के एक निजी अस्पताल में गुर्दे संबंधी बीमारी के इलाज के दौरान निधन हो गया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के सह-स्थापक और राज्य के आदिवासी आंदोलन का प्रमुख चेहरा रहे शिबू सोरेन को झारखंड सशस्त्र पुलिस (जेपीए) के जवानों ने सलामी दी। उनका कड़ी सुरक्षा के बीच पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया।

न्यायालय ने तलाक की अनुमति दी

पत्नी को चार करोड़ का फ्लैट सौंपने का आदेश

नई दिल्ली (भाषा)। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को एक दंपति की तलाक की अर्जा मंजूर कर ली और साथ ही व्यक्ति को निर्देश दिया कि वह अलग रह रही पत्नी को चार करोड़ रुपये का मुंबई स्थित फ्लैट सौंप दे। प्रधान न्यायाधीश बी आर गवाड़, न्यायमूर्ति के विनोद चंदा और न्यायमूर्ति एन जी अजयारिया की पीठ ने व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए (महिला के साथ क्रूरता करना), 406 (आपराधिक विश्वासघात) और धारा 34 के तहत शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को भी रद्द कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि पिछले आठ वर्षों से दोनों पक्षों के बीच कटु संबंध हैं और कई कानूनी कार्यवाहियां लंबित हैं, जिससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि उनकी शादीपूरी तरह से टूट चुकी है। पीठ ने कहा कि हम संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत दायर अर्जा को भी स्वीकार करते हैं।

हिरोशिमा और नागासाकी त्रासदी

हमले में बचे लोग परमाणु हथियारों के खिलाफ जागरूकता फैला रहे

एजेंसी हिरोशिमा

हिरोशिमा और नागासाकी पर 80 साल पहले हुए परमाणु बम हमले में जीवित बचे लोगों ने बढ़ते परमाणु खतरों और वैश्विक नेताओं द्वारा परमाणु हथियारों को स्वीकार किए जाने पर चिंता जताई है। अमेरिका ने छह अगस्त, 1945 को हिरोशिमा पर और उसके तीन दिन बाद नागासाकी पर परमाणु बम से हमला किया था, जिससे उस वर्ष के अंत तक 2,00,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इस घातक हमले में कुछ लोग जीवित बच गए, लेकिन वे विकिरण संबंधी बीमारियों से ग्रस्त हो गए। परमाणु बम हमले के लगभग एक लाख

Sirf Ek कप चाय, कब्ज़ को Tata Bye-Bye

पेट सफा
Laxative Green Tea
fssai
FSSAI NO.: 10924999000065

पेट सफा... तो हर रोग दफा

Good for Digestion
Helps Relieve Constipation

अगर आपका पेट भी सुबह पूरी तरह से साफ नहीं होता तो इससे छुटकारा अब बिल्कुल आसान है, रात को सोते समय 'पेट सफा' Laxative Green Tea का सिर्फ एक कप पीना है, और सुबह आपका पेट होगा, एक झटके में बिल्कुल साफ और Fresh.

Buy Now: amazon | Flipkart | blinkit | 1mg | bigbasket | snapdeal | JioMart

Contact For Dealership 85588 07777 • dealership@divisa.in

ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना की खास तैयारी

वायुसेना-नौसेना ने ब्रह्मोस मिसाइलों का दिया बड़ा ऑर्डर

एजेंसी नई दिल्ली

ब्रह्मोस मिसाइलों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अहम भूमिका निभाई थी और पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठानों को भारी नुकसान पहुंचाया था। भारतीय सेना अब भारत-रूस के ज्वाइंट वेंचर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के लिए बड़ा ऑर्डर दे रही है। एक शीप रक्षा विशेषज्ञ ने बताया कि रक्षा मंत्रालय की एक उच्च स्तरीय बैठक जल्द होगी, जिसमें बड़ी संख्या में ब्रह्मोस मिसाइलों के अधिग्रहण को मंजूरी दी जाएगी। ये खरीद भारतीय नौसेना के युद्धक जहाजों और भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के लिए की जाएगी। ब्रह्मोस एक लंबी दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली है जिसे जमीन, समुद्र और हवा तीनों जगह से प्रक्षेपित (लॉन्च) किया जा सकता है। ब्रह्मोस को डीआरडीओ, भारत और रूस के एनपीओएम द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया

रक्षा मंत्रालय ने दी जानकारी

रक्षा खरीद परिषद ने 67000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को दी मंजूरी

नई दिल्ली (भाषा)। रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को लंबी दूरी तक उड़ान भरने वाले ड्रोन और मिसाइल प्रणालियों की खरीद समेत प्रमुख सैन्य परियोजनाओं को मंजूरी दे दी

जिनपर लगभग 67,000 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद (डीएसी) ने इन परियोजनाओं को मंजूरी दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि भारतीय नौसेना के लिए 'कॉम्पैक्ट ऑटोनॉमस सरफेस क्राफ्ट', 'ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम' और 'लॉवर' की खरीद और 'बराक-1' ज्वाइंट डिफेंस मिसाइल सिस्टम' के उन्नयन को मंजूरी दी गई। उसने कहा कि 'कॉम्पैक्ट ऑटोनॉमस सरफेस क्राफ्ट' की खरीद से भारतीय नौसेना को पनडुब्बी रोधी युद्ध अभियानों में खतरों का पता लगाने, उनका वॉकअप करने और उन्हें बेअसर करने की क्षमता मिलेगी। वायु सेना के लिए, पर्वतीय रडार की खरीद और सक्षम/एवाइडर हथियार प्रणाली के उन्नयन को मंजूरी दी गई। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पर्वतीय रडार की खरीद से पर्वतीय क्षेत्र में सीमाओं पर नजर रखने के साथ-साथ हवाई निगरानी क्षमता में वृद्धि होगी।